

NHRC chairperson calls for vigilance on bonded labour, seeks helpline

PIONEER NEWS SERVICE

■ New Delhi

National Human Rights Commission (NHRC) chairperson Justice V Ramasubramanian (retd) has urged officers to remain vigilant while dealing with cases of bonded labour and emphasised the need to launch a helpline so that labourers can seek help when needed.

The NHRC on July 9 heard online 86 cases of alleged bonded labour in brick kilns across various districts of Haryana, the rights panel said on Friday.

Justice Ramasubramanian



presided over the hearing that saw participation of several senior officials of the state Government and various district magistrates in Haryana.

He said in most of the cases, the records had "not been properly examined" by the Government func-

tionaries concerned.

"Therefore, they did not have credible evidence to declare the labourers as bonded labourers," the rights panel said in a statement. The NHRC chief urged the officers to remain vigilant while dealing with cases of bonded labour.

He further asked them to follow the requirements laid down in the 'Standard Operating Procedure for Identification and Rescue of Bonded Labourers and Prosecution of Offenders', issued by the Ministry of Labour and Employment, vide letter, dated May 14, while constituting a team for an inquiry into a complaint.

He also emphasised the need to launch a helpline so that labourers can seek help when needed to help track the incidents of bonded labour. Samir Kumar, joint secretary, NHRC, highlighted the need to comply with the panel's directions and take

action as per its 'Advisory 2.0 to Identify, Release and Rehabilitate Bonded Labourers'.

The Haryana chief secretary, the labour commissioner and the DMs, presented the bonded labour cases during the hearing. The Commission reviewed the action taken reports submitted by the DMs on the complaints, under its consideration, the statement said.

The state's chief secretary and the labour commissioner assured the NHRC that all the 86 cases would be "reviewed", and the requisite information and reports would be submitted thereafter.

न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन ने श्रमिकों की सहायता हेतु एक हेल्पलाइन की जरूरत पर बल दिया

एनएचआरसी ने हरियाणा के ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी के 86 मामलों की सुनवाई की

हरिभूमि ब्यूरो नई दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी के 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की। एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन ने संयुक्त सचिव समीर कुमार, संयुक्त रजिस्ट्रार (कानून) इंद्रजीत कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सुनवाई की अध्यक्षता की। सुनवाई में हरियाणा सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, श्रम आयुक्त विजयकुमार भाविकट्टी और सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) शामिल थे।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमणियन ने कहा कि अधिकतर मामलों में संबंधित सरकारी अधिकारियों ने अभिलेखों की ठीक से जांच नहीं की थी। इसलिए, उनके पास श्रमिकों को बंधुआ मजदूर घोषित करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य नहीं थे। उन्होंने अधिकारियों से बंधुआ मजदूरी के मामलों से निपटते समय सतर्क रहने की बात कही।

उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत की जांच के लिए टीम का गठन करते समय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 मई 2026 को जारी बंधुआ मजदूरों की पहचान और बचाव तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए मानक

संचालन प्रक्रिया में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन किया जाए। उन्होंने बंधुआ मजदूरी की घटनाओं पर नजर रखने में मदद के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करने की जरूरत पर भी बल दिया ताकि श्रमिक जरूरत पड़ने पर सहायता प्राप्त कर सकें।

एनएचआरसी के संयुक्त सचिव समीर कुमार ने एनएचआरसी के निर्देशों का पालन करने और 'बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास हेतु जारी सलाह 2.0' के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया। सुनवाई के दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव, श्रम आयुक्त और जिला प्रशासकों ने बंधुआ मजदूरी के मामले प्रस्तुत किए। आयोग ने अपने समक्ष विचाराधीन शिकायतों पर जिला प्रशासकों की जमा की गई कार्रवाई रिपोर्टों (एटीआर) की समीक्षा की।

मुख्य सचिव और श्रम आयुक्त ने मानवाधिकार आयोग को आश्वासन दिया कि सभी 86 मामलों की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद आवश्यक जानकारी और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने एनएचआरसी को यह भी आश्वासन दिया कि बंधुआ मजदूरों से संबंधित मामलों में तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और लागू कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

कहा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करे हरियाणा सरकार
एचटेट परीक्षा की अव्यवस्था ने हरियाणा की भर्ती प्रणाली पर खड़े किए गंभीर

हरिभूमि ब्यूरो नई दिल्ली

सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) में व्यापक आपत्तियों और परीक्षा संचालन में गंभीर खामियों का आरोप लगाते हुए कहा है कि यह केवल एक परीक्षा की त्रुटि नहीं, बल्कि प्रदेश की भर्ती व्यवस्था पर जनता के भरोसे को कमजोर करने वाला मामला है। कुमारी सैलजा ने शुक्रवार को मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि एचटेट के तीनों स्तरों की परीक्षा में लगभग 17 हजार आपत्तियां दर्ज हुई हैं। अनेक अभ्यर्थियों ने प्रश्नों के गलत विकल्प, प्रश्न संख्या में त्रुटियां तथा अन्य तकनीकी कमियों की शिकायत की है। यदि इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां सामने आती हैं तो यह परीक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्नचिह्न

लगाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा वर्षों तक तैयारी करता है, आर्थिक बोझ उठाता है और मानसिक तनाव झेलता है। ऐसे में परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्रश्नपत्र, मूल्यांकन और पूरी प्रक्रिया त्रुटिरहित हो। यदि गलतियां प्रशासन की हैं तो उनकी सजा युवाओं को नहीं मिलनी चाहिए। कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस की स्पष्ट नीति है कि योग्य अभ्यर्थियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार को स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों से निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और जिन प्रश्नों में त्रुटियां सिद्ध हों, वहां ऐसा निर्णय लिया जाए जिससे किसी भी अभ्यर्थी का नुकसान न हो। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएं तथा जवाबदेही भी तय की जाए।

पहली बारिश में डूब गई मिलेनियम सिटी, स्मार्ट सिटी का दावा फिर हुआ बेनकाब : सैलजा

कुमारी सैलजा ने कहा कि हर साल मानसून आता है और हर साल गुरुग्राम जलभराव, ट्रैफिक जाम और बदइंतजामी की तस्वीरों से सुर्खियों में आ जाता है। इस बार भी मात्र एक घंटे की बारिश ने तथाकथित स्मार्ट सिटी मॉडल की पूरी हकीकत जनता के सामने ला दी। सांसद ने कहा कि दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलभराव और सड़क धंसने जैसी घटनाएं, कई किलोमीटर लंबे जाम, हजारों लोगों का घंटों फंसे रहना तथा बच्चों को स्कूल से गोद में उठाकर घर ले जाने की नौबत यह साबित करती है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद शहरी आधारभूत ढांचा बेहद कमजोर है।

मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज, डीजीपी से मांगा जवाब

कार्रवाई

मेरठ, प्रमुख संवाददाता। मेरठ के थप्पड़ कांड और लाठीचार्ज का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर गरमा गया है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रिटायर्ड आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की ओर से राज्य मानवाधिकार आयोग को भेजी शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। दूसरी ओर, भोपाल के डॉ. अंबेडकर जनकल्याण समिति की ओर से भेजी गई शिकायत का भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते

- रिटायर्ड आईपीएस ने मेरठ पुलिस के खिलाफ भेजी थी शिकायत
- भोपाल के डॉ. अंबेडकर जनकल्याण समिति ने भी केस दर्ज कराने की मांग की थी

हुए केस दर्ज कर लिया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, साथ ही टिप्पणी भी की है कि मौजूद वीडियो आधार पर यह प्रकरण प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों के उल्लंघन का पाया

डीजीपी और सचिव से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

लाठीचार्ज और थप्पड़ कांड को लेकर भोपाल की डॉ. अंबेडकर जनकल्याण समिति ने भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी थी। वीडियो साक्ष्य भी शिकायत के साथ भेजे गए थे। इस पर आयोग ने केस संख्या 7581/24/54/2026 दर्ज कर लिया है, साथ ही यूपी के डीजीपी और सचिव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि प्रथम दृष्टया शिकायत के साथ जो वीडियो साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनके अनुसार मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रकरण पाया गया है। 15 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है।

गया है।

रोहता के थिरोट गांव निवासी ललिता गौतम की हत्या के मामले में बाकी आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर 8 जुलाई को मेरठ कमिशनरी

पर धरने के दौरान पुलिस ने लाठियां फटकारी थीं और एसएसपी ने लोगों पर थप्पड़ बरसाए थे। बंदी वाहन में बंद एक आरोपी रवि गौतम को एसएसपी द्वारा पीटने का वीडियो भी

वायरल हुआ था।

रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने मारपीट, थप्पड़बाजी और लाठीचार्ज की तमाम वीडियो के साथ शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग में की थी। राज्य मानव अधिकार आयोग ने इसे लेकर केस संख्या 14615/24/54/2026 दर्ज कर लिया है। अमिताभ ठाकुर ने शिकायत में कहा था कि एसएसपी मेरठ द्वारा मारपीट किया जाना गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और जवाबदेही का विषय है।

NHRC chairperson calls for vigilance on bonded labour, seeks helpline

PIONEER NEWS SERVICE

■ New Delhi

National Human Rights Commission (NHRC) chairperson Justice V Ramasubramanian (retd) has urged officers to remain vigilant while dealing with cases of bonded labour and emphasised the need to launch a helpline so that labourers can seek help when needed.

The NHRC on July 9 heard online 86 cases of alleged bonded labour in brick kilns across various districts of Haryana, the rights panel said on Friday.

Justice Ramasubramanian



presided over the hearing that saw participation of several senior officials of the state Government and various district magistrates in Haryana.

He said in most of the cases, the records had "not been properly examined" by the Government func-

tionaries concerned.

"Therefore, they did not have credible evidence to declare the labourers as bonded labourers," the rights panel said in a statement. The NHRC chief urged the officers to remain vigilant while dealing with cases of bonded labour.

He further asked them to follow the requirements laid down in the 'Standard Operating Procedure for Identification and Rescue of Bonded Labourers and Prosecution of Offenders', issued by the Ministry of Labour and Employment, vide letter, dated May 14, while constituting a team for an inquiry into a complaint.

He also emphasised the need to launch a helpline so that labourers can seek help when needed to help track the incidents of bonded labour. Samir Kumar, joint secretary, NHRC, highlighted the need to comply with the panel's directions and take

action as per its 'Advisory 2.0 to Identify, Release and Rehabilitate Bonded Labourers'.

The Haryana chief secretary, the labour commissioner and the DMs, presented the bonded labour cases during the hearing. The Commission reviewed the action taken reports submitted by the DMs on the complaints, under its consideration, the statement said.

The state's chief secretary and the labour commissioner assured the NHRC that all the 86 cases would be "reviewed", and the requisite information and reports would be submitted thereafter.

NHRC chairperson calls for vigilance on bonded labour, seeks helpline

PIONEER NEWS SERVICE

■ New Delhi

National Human Rights Commission (NHRC) chairperson Justice V Ramasubramanian (retd) has urged officers to remain vigilant while dealing with cases of bonded labour and emphasised the need to launch a helpline so that labourers can seek help when needed.

The NHRC on July 9 heard online 86 cases of alleged bonded labour in brick kilns across various districts of Haryana, the rights panel said on Friday.

Justice Ramasubramanian



presided over the hearing that saw participation of several senior officials of the state Government and various district magistrates in Haryana.

He said in most of the cases, the records had "not been properly examined" by the Government func-

tionaries concerned.

"Therefore, they did not have credible evidence to declare the labourers as bonded labourers," the rights panel said in a statement. The NHRC chief urged the officers to remain vigilant while dealing with cases of bonded labour.

He further asked them to follow the requirements laid down in the 'Standard Operating Procedure for Identification and Rescue of Bonded Labourers and Prosecution of Offenders', issued by the Ministry of Labour and Employment, vide letter, dated May 14, while constituting a team for an inquiry into a complaint.

He also emphasised the need to launch a helpline so that labourers can seek help when needed to help track the incidents of bonded labour. Samir Kumar, joint secretary, NHRC, highlighted the need to comply with the panel's directions and take

action as per its 'Advisory 2.0 to Identify, Release and Rehabilitate Bonded Labourers'.

The Haryana chief secretary, the labour commissioner and the DMs, presented the bonded labour cases during the hearing. The Commission reviewed the action taken reports submitted by the DMs on the complaints, under its consideration, the statement said.

The state's chief secretary and the labour commissioner assured the NHRC that all the 86 cases would be "reviewed", and the requisite information and reports would be submitted thereafter.

NHRC issues notice to UP Home Secy, DGP over lathi-charge on protesters in Meerut

PRESS TRSUT OF INDIA

■ New Delhi

The NHRC has issued a notice to the Uttar Pradesh DGP and the state's home secretary in the wake of a complaint alleging that police resorted to "unprovoked, brutal lathi-charge" during a "peaceful" public demonstration in Meerut, inflicting severe injuries on multiple protesters, according to the proceedings of the case.

The allegations made in the complaint prima facie seem to be violations of the victims' human rights, it said, adding the National Human Rights Commission (NHRC)

has sought an action taken report within 15 days.

An NHRC bench presided by its member Priyank Kanoongo took cognisance of the case under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, according to the proceedings dated July 10.

The complainant, Sunil Ahirwar of Bhopal, alleged that "during a peaceful public demonstration in Meerut demanding justice in the Lalita Gautam murder case, police unleashed an unprovoked, brutal lathi-charge, inflicting severe physical injuries on multiple protesters".

The complainant also

alleged that widely circulated videos depicted senior police officers "committing custodial torture by mercilessly beating defenceless individuals", who had already been taken into custody, demonstrating a "complete breakdown" of rule of law and structural violation of personal dignity, the proceedings said.

The complainant sought immediate intervention by the NHRC to register a complaint, and demanded that the chief secretary and the DGP submit a comprehensive report, initiate an independent inquiry into the case, and verify the viral videos to

establish individual accountability, provide immediate medical rehabilitation and statutory financial compensation to all the injured, and order swift criminal and disciplinary action against the "defaulting police officers", the proceedings said.

The registry is directed to issue a notice to the home secretary of Uttar Pradesh, and its DGP, to submit an action taken report within 15 days for perusal of the Commission, they added.

A copy of the proceedings is to be transmitted to the chief secretary to ensure necessary compliance in the matter, the proceedings said.

NHRC: Helpline can aid bonded labour

NEW DELHI: NHRC chairperson Justice V Ramasubramanian (retd) has urged officers to remain vigilant while dealing with cases of bonded labour and emphasised the need to launch a helpline so that labourers can seek help when needed. The NHRC on July 9 heard online 86 cases of alleged bonded labour in brick kilns across various districts of Haryana, the rights panel said.

NHRC issues notice to U.P. officials over ‘police excesses’

The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday issued notices to the Uttar Pradesh Director-General of Police (DGP) and the State Home Secretary over allegations that the police used excessive force against protesters during the July 8 protest in Meerut demanding justice in the murder case of a Dalit woman. The notice was issued after an NHRC Bench headed by member Priyank Kanoongo took cognisance of a complaint filed by Sunil Ahirwar of Bhopal under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993. The Commission directed the Home Secretary and the DGP to submit an action taken report within 15 days for its consideration.

NHRC chairperson calls for vigilance on bonded labour, seeks helpline

PIONEER NEWS SERVICE

■ New Delhi

National Human Rights Commission (NHRC) chairperson Justice V Ramasubramanian (retd) has urged officers to remain vigilant while dealing with cases of bonded labour and emphasised the need to launch a helpline so that labourers can seek help when needed.

The NHRC on July 9 heard online 86 cases of alleged bonded labour in brick kilns across various districts of Haryana, the rights panel said on Friday.

Justice Ramasubramanian



presided over the hearing that saw participation of several senior officials of the state Government and various district magistrates in Haryana.

He said in most of the cases, the records had "not been properly examined" by the Government func-

tionaries concerned.

"Therefore, they did not have credible evidence to declare the labourers as bonded labourers," the rights panel said in a statement. The NHRC chief urged the officers to remain vigilant while dealing with cases of bonded labour.

He further asked them to follow the requirements laid down in the 'Standard Operating Procedure for Identification and Rescue of Bonded Labourers and Prosecution of Offenders', issued by the Ministry of Labour and Employment, vide letter, dated May 14, while constituting a team for an inquiry into a complaint.

He also emphasised the need to launch a helpline so that labourers can seek help when needed to help track the incidents of bonded labour. Samir Kumar, joint secretary, NHRC, highlighted the need to comply with the panel's directions and take

action as per its 'Advisory 2.0 to Identify, Release and Rehabilitate Bonded Labourers'.

The Haryana chief secretary, the labour commissioner and the DMs, presented the bonded labour cases during the hearing. The Commission reviewed the action taken reports submitted by the DMs on the complaints, under its consideration, the statement said.

The state's chief secretary and the labour commissioner assured the NHRC that all the 86 cases would be "reviewed", and the requisite information and reports would be submitted thereafter.

NHRC reviews 86 alleged bonded labour cases in Haryana brick kilns

GK News Service

New Delhi, Jul 10

The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday conducted an online hearing of 86 cases of alleged bonded labour in brick kilns across various districts of Haryana, with Chairperson Justice V. Ramasubramanian directing officials to strictly follow the prescribed procedures for identifying and rescuing bonded labourers.

The hearing was attended by Haryana Chief Secretary Anurag Rastogi, Labour Commissioner Vijaykumar Bhavikatti, District Magistrates from all districts, and senior NHRC officials, including Joint Secretary Samir Kumar and Joint Registrar (Law) Indrajeet Kumar.

Justice Ramasubramanian observed that records in many cases had not been properly examined, resulting

in a lack of credible evidence to establish bonded labour. He urged officials to remain vigilant, adhere to the Standard Operating Procedure issued by the Ministry of Labour and Employment on May 14, 2026, while conducting inquiries, and consider launching a helpline to enable labourers to report cases of exploitation.

NHRC Joint Secretary Samir Kumar stressed compliance with the Commission's "Advisory 2.0 to Identify, Release and Rehabilitate Bonded Labourers." After reviewing Action Taken Reports submitted by district authorities, the Haryana Chief Secretary and Labour Commissioner assured the Commission that all 86 cases would be re-examined and fresh reports submitted. They also pledged full compliance with Supreme Court directions and applicable laws to ensure prompt action in bonded labour cases.

NHRC chairperson calls for vigilance on bonded labour, seeks helpline

PIONEER NEWS SERVICE

■ New Delhi

National Human Rights Commission (NHRC) chairperson Justice V Ramasubramanian (retd) has urged officers to remain vigilant while dealing with cases of bonded labour and emphasised the need to launch a helpline so that labourers can seek help when needed.

The NHRC on July 9 heard online 86 cases of alleged bonded labour in brick kilns across various districts of Haryana, the rights panel said on Friday.

Justice Ramasubramanian



presided over the hearing that saw participation of several senior officials of the state Government and various district magistrates in Haryana.

He said in most of the cases, the records had "not been properly examined" by the Government func-

tionaries concerned.

"Therefore, they did not have credible evidence to declare the labourers as bonded labourers," the rights panel said in a statement. The NHRC chief urged the officers to remain vigilant while dealing with cases of bonded labour.

He further asked them to follow the requirements laid down in the 'Standard Operating Procedure for Identification and Rescue of Bonded Labourers and Prosecution of Offenders', issued by the Ministry of Labour and Employment, vide letter, dated May 14, while constituting a team for an inquiry into a complaint.

He also emphasised the need to launch a helpline so that labourers can seek help when needed to help track the incidents of bonded labour. Samir Kumar, joint secretary, NHRC, highlighted the need to comply with the panel's directions and take

action as per its 'Advisory 2.0 to Identify, Release and Rehabilitate Bonded Labourers'.

The Haryana chief secretary, the labour commissioner and the DMs, presented the bonded labour cases during the hearing. The Commission reviewed the action taken reports submitted by the DMs on the complaints, under its consideration, the statement said.

The state's chief secretary and the labour commissioner assured the NHRC that all the 86 cases would be "reviewed", and the requisite information and reports would be submitted thereafter.

Bengal rape-murder: 5 more held for mob violence; investigation sought into encounter

Shiv Sahay Singh
KOLKATA

The West Bengal police have taken into custody five more suspects in connection with the mob violence that erupted after the alleged rape and murder of an 12-year-old girl in Baruipur, raising the total arrests in the case to 35, officials said on Friday.

The five were arrested during overnight raids conducted in Baruipur in South 24 Parganas, officials said, adding that efforts are under way to apprehend other accused.

Four FIRs have been registered, one in the rape and murder of the 12-year-old girl, and three more in the violence, attack on police outpost and lynching of a youth.

The Criminal Investigation Department of West Bengal police are investigating the encounter. On Friday, a team of forensic experts had visited the site of encounter.

Chief Minister Suvendu Adhikari, who had visited Baruipur earlier this week and met the victim's family members, is likely to visit the area again next week.

In the rape and murder case, police so far arrested four persons - prime accused Anand Sardar, Prabhas Mondal, Dibakar Sardar and Kabir Molla. Mondal was killed in a police 'encounter' on Tuesday night after he allegedly attempted to snatch a service firearm from a police officer and flee during the recon-

struction of the crime.

Several civil rights organisation, meanwhile, have demanded an investigation into the encounter. "It is hoped that the Chief Minister will abide by the Supreme Court's directives, ensure a genuine investigation into the encounter death, take appropriate action, and secure exemplary punishment for the guilty through due legal process for all crimes, including the rape-murder in Baruipur and deaths caused by mob lynching," said Subha Protim Roy Chowdhury of Amra Ek Sachetan Prayas. Association for Protection of Democratic Rights (APDR) has called for investigation by a sitting Calcutta High Court judge.

"Fake encounter"

"At this moment, we feel that the encounter was fake. We demand that all the three incidents be investigated by a sitting Calcutta High Court judge," Ranajit Sur, vice-president of APDR, said.

Kirity Roy of MASUM said the police reconstruction of crime without any cameras at 1 a.m. is not possible.

"In accordance with the Constitution, the Supreme Court's *PUC v. Maharashtra (2014)* and *DK Basu v. Govt. of West Bengal (1997)* and National Human Rights Commission guidelines on encounter death, an FIR should be lodged against the Baruipur police in the killing of Prabhas Mondal," Mr. Roy said.

मणिपाल छात्र मौत मामले में एनएचआरसी सख्त, तीसी से दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

जमशेदपुर | बेंगलुरु स्थित मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे छात्र की संदिग्ध मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है। जमशेदपुर निवासी अंजनी कुमार मिश्रा की शिकायत पर आयोग ने मामले को प्रथमदृष्टया मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा मानते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति और बेंगलुरु पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों को शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर दो सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि छात्र की मौत की निष्पक्ष जांच नहीं की गई। अब तक परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई और न ही आरोपपत्र दाखिल किया गया।

एनएचआरसी का यूपी के गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मेरठ में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और गृह सचिव को शुक्रवार नोटिस जारी किया है और 15 दिनों के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। एनएचआरसी ने यह कार्रवाई मेरठ में शांतिपूर्ण सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान बगैर उकसावे के बेरहमी से पुलिस के लाठीचार्ज करने की शिकायत पर की। दरअसल, इस मामले की शुक्रवार को हुई कार्यवाही में आयोग ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं। प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता में एनएचआरसी की पीठ ने

मामले में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया। शिकायतक में भोपाल के रहने वाले शिकायतकर्ता सुनील अहिरवार ने आरोप लगाया कि ललिता गौतम हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर मेरठ में एक शांतिपूर्ण सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बगैर उकसावे के बेरहमी से लाठीचार्ज किया। इसके कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर शारीरिक चोटें आईं। इसके साथ ही घटना के बड़े पैमाने पर प्रसारित वीडियो में बरिष्ठ पुलिस अधिकारी हिरासत में लिए गए निहत्थे लोगों को बेरहमी से पीटकर यातना देते हुए दिखाए। इसे लेकर उन्होंने एनएचआरसी से तत्काल दखल की मांग की थी। एजेंसी

Source: <https://news.abplive.com/education/26-telangana-residential-school-students-fall-ill-after-breakfast-investigation-underway-1855632>

English NewsEducation26 Telangana Residential School Students Fall Ill After Breakfast, Investigation Underway

26 Telangana Residential School Students Fall Ill After Breakfast, Investigation Underway

26 Students at a residential school in Telangana fell ill after eating breakfast and received prompt medical attention. Authorities have launched an inquiry to determine the cause of the incident.

Written By : IANS | Updated at : 10 Jul 2026 01:03 PM (IST)

In yet another incident of food poisoning in government-operated residential schools in Telangana, 26 students were taken ill at a tribal residential school in Nagarkurnool district on Thursday.

The students fell ill after breakfast at Chenchu Tribal Government Residential School in Mannanur Village of Amrabad Mandal.

The students, shortly after breakfast, experienced symptoms of diarrhoea. The affected students were rushed to the Mannanur Government Hospital and then taken to other hospital due to unavailability of sufficient beds.

The students were made to lie on the floor as the hospital for treatment as the hospital administration cited lack of beds. Parents registered their protest with the authorities over lack of facilities at the hospital.

The affected students were later shifted to Achampet Area Hospital.

Some of the students said that they saw insects in the 'khichdi' served to them in the breakfast.

The incident comes just a few days after food poisoning incident at Kamareddy Gurukul School. As many as 33 students were hospitalised after they fell sick following lunch.

Two incidents of food poisoning in residential schools since the beginning of the new academic year has once again spotlighted the concerns over the safety of food served to the students at residential schools.

In July last year, National Human Rights Commission (NHRC) had directed the state government to investigate reports of over 800 incidents of suspected food poisoning and submit a detailed report.

NHRC chairperson Justice V. Ramasubramanian said the Commission had taken serious note of the poisoning cases. It came to NHRC's attention that around 48 student deaths involving 886 incidents of food poisoning in gurukul schools across Telangana have occurred.

Meanwhile, students at Telangana University in Nizamabad district staged a massive protest on Thursday demanding a resolution to the drinking water crisis.

Expressing their distress over the lack of a proper water supply in recent days, they protested by blocking an RTC

bus that had arrived at the university.

Frequently Asked Questions

Has the National Human Rights Commission (NHRC) addressed food safety in these schools?

Yes, the NHRC directed the state government to investigate over 800 suspected food poisoning incidents last year. They noted 48 student deaths across 886 incidents in gurukul schools.

Source: https://www.socialnews.xyz/2026/07/10/nhrc-hears-86-cases-of-alleged-bonded-labour-in-haryana-brick-kilns/#google_vignette

Home » Law » NHRC hears 86 cases of alleged bonded labour in Haryana brick kilns

NHRC hears 86 cases of alleged bonded labour in Haryana brick kilns

Posted By: Gopi July 10, 2026

New Delhi, July 10 (SocialNews.XYZ) National Human Rights Commission (NHRC) Chairperson Justice V. Ramasubramanian heard 86 cases of alleged bonded labour in brick kilns across various districts of Haryana during an online hearing, directing officials to launch a helpline to help labourers in distress, an official said on Friday.

During the hearing on Thursday on alleged bonded labour in brick kilns across various districts of Haryana, Chief Secretary Anurag Rastogi and other officials assured the NHRC that all 86 cases would be reviewed and the requisite information and reports would be submitted thereafter.

They also assured the Commission that full compliance with the directions of the Supreme Court and the applicable laws would be ensured to facilitate immediate remedial action in cases relating to bonded labour, a statement said.

Chairperson Justice Ramasubramanian, while presiding over the hearing, said that in most cases, the records had not been properly examined by the concerned government functionaries.

Therefore, they did not have credible evidence to declare the labourers as bonded labourers, he said.

He urged the officers to remain vigilant while dealing with cases of bonded labour, asking them to follow the requirements laid down in the Standard Operating Procedure for Identification and Rescue of Bonded Labourers and Prosecution of Offenders, issued by the Ministry of Labour and Employment, while constituting the team for the enquiry into the complaint.

He also emphasised the need to launch a helpline so that labourers could seek help when needed and incidents of bonded labour could be tracked.

Samir Kumar, Joint Secretary, NHRC, highlighted the need to comply with the NHRC directions and take action in accordance with its 'Advisory 2.0 to Identify, Release and Rehabilitate Bonded Labourers.'

The hearing was attended by senior functionaries of the state government, including Labour Commissioner Vijaykumar Bhavikatti and the District Magistrates (DMs) of all the districts.

The Haryana Chief Secretary, the Labour Commissioner and the DMs presented the bonded labour cases during the hearing. The Commission reviewed the Action Taken Reports (ATRs) submitted by the DMs on the complaints under its consideration, the statement said.

Source: <https://theprint.in/india/nhrc-chief-says-helpline-can-aid-victims-of-bonded-labour/2983020/?amp>

Commission (NHRC) on July 9 heard online 86 cases of alleged
PTI 10 July, 2026 03:50 pm IST

New Delhi, Jul 10 (PTI) NHRC chairperson Justice V Ramasubramanian (retd) has urged officers to remain vigilant while dealing with cases of bonded labour and emphasised the need to launch a helpline so that labourers can seek help when needed.

The National Human Rights Commission (NHRC) on July 9 heard online 86 cases of alleged bonded labour in brick kilns across various districts of Haryana, the rights panel said on Friday.

Justice Ramasubramanian presided over the hearing that saw participation of several senior officials of the state government and various district magistrates in Haryana.

He said in most of the cases, the records had “not been properly examined” by the government functionaries concerned. “Therefore, they did not have credible evidence to declare the labourers as bonded labourers,” the rights panel said in a statement.

The NHRC chief urged the officers to remain vigilant while dealing with cases of bonded labour.

He further asked them to follow the requirements laid down in the ‘Standard Operating Procedure for Identification and Rescue of Bonded Labourers and Prosecution of Offenders’, issued by the Ministry of Labour and Employment, vide letter, dated May 14, while constituting a team for an inquiry into a complaint.

He also emphasised the need to launch a helpline so that labourers can seek help when needed to help track the incidents of bonded labour.

Samir Kumar, joint secretary, NHRC, highlighted the need to comply with the panel’s directions and take action as per its ‘Advisory 2.0 to Identify, Release and Rehabilitate Bonded Labourers’.

The Haryana chief secretary, the labour commissioner and the DMs, presented the bonded labour cases during the hearing. The Commission reviewed the action taken reports submitted by the DMs on the complaints, under its consideration, the statement said.

The state’s chief secretary and the labour commissioner assured the NHRC that all the 86 cases would be “reviewed”, and the requisite information and reports would be submitted thereafter. They also assured the Commission that full compliance with the directions of the Supreme Court and the applicable laws would be ensured to facilitate “immediate remedial action” in cases relating to bonded labour, it said. PTI KIND PRK

Source: <https://www.khabarfast.com/nhrc-hearing-regarding-bonded-labor-in-haryana-officials-asked-to-be-cautious-in-investigation>

हरियाणा के बंधुआ मजदूरी को लेकर NHRC की सुनवाई, अधिकारियों को जांच में सतर्कता बरतने को कहा
Shivani Jha | Updated: 10 Jul, 2026

Haryana News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), भारत ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी के 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यन ने संयुक्त सचिव समीर कुमार, संयुक्त रजिस्ट्रार (कानून) इंद्रजीत कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सुनवाई की अध्यक्षता की। सुनवाई में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, श्रम आयुक्त विजयकुमार भाविकट्टी और सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) शामिल थे।

अभिलेखों की ठीक से जांच नहीं की गई थी

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने कहा कि अधिकांश मामलों में संबंधित सरकारी अधिकारियों द्वारा अभिलेखों की ठीक से जांच नहीं की गई थी। इसलिए, उनके पास मजदूरों को बंधुआ मजदूर घोषित करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य नहीं थे। विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने अधिकारियों से बंधुआ मजदूरी के मामलों से निपटते समय सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि शिकायत की जांच के लिए टीम का गठन करते समय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 14 मई को जारी पत्र के माध्यम से बंधुआ मजदूरों की पहचान और बचाव तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन किया जाए।

हेल्पलाइन शुरू करने की जरूरत

उन्होंने बंधुआ मजदूरी की घटनाओं पर नजर रखने में मदद के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि मजदूर जरूरत पड़ने पर सहायता प्राप्त कर सकें। विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रीय श्रम आयोग (NHRC) के संयुक्त सचिव समीर कुमार ने एनएचआरसी के निर्देशों का पालन करने और 'बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास के लिए एडवाइजरी 2.0' के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

एटीआर की समीक्षा की गई

सुनवाई के दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव, श्रम आयुक्त और जिला प्रशासकों ने बंधुआ मजदूरी के मामले प्रस्तुत किए। आयोग ने अपने विचाराधीन शिकायतों पर जिला प्रशासकों द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) की समीक्षा की। मुख्य सचिव और श्रम आयुक्त ने आयोग को आश्वासन दिया कि सभी 86 मामलों की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद आवश्यक जानकारी और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएंगी। उन्होंने आयोग को यह भी आश्वासन दिया कि बंधुआ मजदूरी से संबंधित मामलों में तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और लागू कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

Source: <https://liveindia.tv/nation/nhrc-issues-notice-over-meerut-protest-violence/>

NHRC Issues Notice Over Meerut Protest Violence

By Srishty Mishra Jul 10, 2026

The National Human Rights Commission has sought a report from the Uttar Pradesh government

July 10, 2026: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Uttar Pradesh Director General of Police (DGP) and the state's Home Secretary over allegations that police used excessive force during a protest in Meerut. Taking cognisance of a complaint under the Protection of Human Rights Act, the Commission observed that the allegations, if true, prima facie indicate violations of human rights and directed the authorities to submit an action taken report within 15 days.

The complaint, filed by Sunil Ahirwar of Bhopal, alleged that police carried out an "unprovoked and brutal lathi-charge" on demonstrators who had gathered peacefully to demand justice in the Lalita Gautam murder case. It further claimed that several protesters suffered serious injuries and that viral videos showed senior police officers allegedly assaulting detained individuals, raising concerns over custodial violence and misuse of force.

The complainant urged the NHRC to order an independent inquiry, verify the authenticity of the viral videos, identify the officials responsible, and ensure criminal and departmental action against those found guilty. The plea also sought medical assistance and financial compensation for the injured protesters. The Commission has directed that a copy of its proceedings be sent to the Uttar Pradesh Chief Secretary to ensure compliance with its directions.

Source: <https://www.msn.com/en-in/news/India/none-found-on-ground-haryana-officials-as-nhrc-flags-84-cases-of-bonded-labour-in-state/ar-AA27B6Pf?apiversion=v2&domshim=1&noservercache=1&noservertelemetry=1&batchservertelemetry=1&renderwebcomponents=1&wcs>

None found on ground': Haryana officials as NHRC flags 84 cases of bonded labour in state
Story by Aditi Tandon • 21h •

After the National Human Rights Commission flagged 84 cases of bonded labour across Haryana, state officials today told the NHRC that none of these cases could be detected when inspection teams were sent to the ground for checks.

This position was taken by all district magistrates of Haryana who attended a virtual meeting convened by the NHRC to review the flagged bonded labour cases. Present also in the meeting was the Haryana Chief Secretary and top state officials of the labour department.

Speaking exclusively to The Tribune after the meeting, NHRC Chairperson Justice V Ramasubramanian (Retd) said the commission had now decided to issue a detailed advisory to Haryana and all other states on how to change the existing government approach to the detection of bonded labour.

"We had called a virtual meeting with Haryana officials after we found their previous responses to the matter unsatisfactory. When we received these 84 complaints of bonded labour mostly across Haryana's brick kilns, we issued notices to district magistrates concerned. They wrote back saying they could not find any case of bonded labour in the state in their inspections. We were not satisfied with the replies and so this virtual meeting was called today. All DMs attended and all stuck to their previous stand that no case of bonded labour could be found in Haryana upon ground inspection," Justice Ramasubramanian said.

NHRC said Haryana officials, however, admitted that inspection teams were not constituted with independent witnesses — a requirement under the SOPs. The commission has now decided to issue a detailed advisory to Haryana and all other states to follow proper standard operating procedures in the matter of constituting inspection teams to assess bonded labour cases.

"We will also say in the advisory that the inspectors should tally production volumes on site with the number of workers registered at the unit being inspected. If the volumes are high and worker numbers are low there is a clear presumption of bonded labour because there is a mismatch," Justice Ramasubramanian said.

He said the commission had recently conducted a similar meeting on bonded labour status in UP which is the worst hit with 216 cases. After Haryana, the NHRC will also review bonded labour cases of Punjab.

The Chairperson lamented that while it has been 50 years since India enacted The Bonded System Abolition Act in 1976, the practice is still prevalent and state governments are still finding it difficult to detect.

Justice Ramasubramanian said at the Haryana meeting today, the abolition of bonded labour was one segment where all three pillars of democracy have intervened -- Parliament has enacted laws, judiciary has passed orders and executive has issued standard operating procedures.

Source: <https://menafn.com/1111379804/NHRC-Hears-86-Cases-Of-Alleged-Bonded-Labour-In-Haryana-Brick-Kilns>

NHRC Hears 86 Cases Of Alleged Bonded Labour In Haryana Brick Kilns

Date 2026-07-10 08:31:14

(MENAFN- IANS) New Delhi, July 10 (IANS) National Human Rights Commission (NHRC) Chairperson Justice V. Ramasubramanian heard 86 cases of alleged bonded labour in brick kilns across various districts of Haryana during an online hearing, directing officials to launch a helpline to help labourers in distress, an official said on Friday.

During the hearing on Thursday on alleged bonded labour in brick kilns across various districts of Haryana, Chief Secretary Anurag Rastogi and other officials assured the NHRC that all 86 cases would be reviewed and the requisite information and reports would be submitted thereafter.

They also assured the Commission that full compliance with the directions of the Supreme Court and the applicable laws would be ensured to facilitate immediate remedial action in cases relating to bonded labour, a statement said.

Chairperson Justice Ramasubramanian, while presiding over the hearing, said that in most cases, the records had not been properly examined by the concerned government functionaries.

Therefore, they did not have credible evidence to declare the labourers as bonded labourers, he said.

He urged the officers to remain vigilant while dealing with cases of bonded labour, asking them to follow the requirements laid down in the Standard Operating Procedure for Identification and Rescue of Bonded Labourers and Prosecution of Offenders, issued by the Ministry of Labour and Employment, while constituting the team for the enquiry into the complaint.

He also emphasised the need to launch a helpline so that labourers could seek help when needed and incidents of bonded labour could be tracked.

Samir Kumar, Joint Secretary, NHRC, highlighted the need to comply with the NHRC directions and take action in accordance with its 'Advisory 2.0 to Identify, Release and Rehabilitate Bonded Labourers.'

The hearing was attended by senior functionaries of the state government, including Labour Commissioner Vijaykumar Bhavikatti and the District Magistrates (DMs) of all the districts.

The Haryana Chief Secretary, the Labour Commissioner and the DMs presented the bonded labour cases during the hearing. The Commission reviewed the Action Taken Reports (ATRs) submitted by the DMs on the complaints under its consideration, the statement said.

Source: <https://www.thehawk.in/news/india/nhrc-seeks-probe-report-on-alleged-excessive-force-by-up-police-in-meerut-protest>

NHRC seeks probe report on alleged excessive force by UP Police in Meerut protest

NHRC Probes Alleged Excessive Force by UP Police During Meerut Protest

The Hawk Jul 10, 2026, 12:26 PM(Updated Jul 10, 2026, 01:56 PM)

New Delhi, July 10 (IANS) The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of a complaint alleging excessive use of force by the Uttar Pradesh Police during a protest in Meerut demanding justice in the Lalita Gautam murder case.

A Bench presided over by NHRC Member Priyank Kanoongo has issued notices to the Home Secretary and the Director General of Police (DGP), Uttar Pradesh, directing them to submit an Action Taken Report (ATR) within 15 days.

The action has been initiated under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, which empowers the Commission to inquire into alleged violations of human rights.

The complaint, filed by Dr Ambedkar Jan Kalyan Samiti, Bhopal, alleged that the local police resorted to an unprovoked and brutal lathi-charge during a peaceful public demonstration in Meerut, causing serious injuries to several protesters.

It further alleged that widely circulated videos showed senior police officials assaulting individuals who had already been taken into custody, amounting to custodial torture and a serious violation of personal dignity and the rule of law.

The complainant sought the NHRC's intervention, requesting that the Uttar Pradesh government be directed to submit a comprehensive report, conduct an independent inquiry into the alleged use of force, verify the authenticity of the viral videos to fix individual accountability, provide medical rehabilitation and statutory compensation to the injured victims, and initiate criminal as well as departmental proceedings against the police personnel found responsible.

After examining the complaint, the apex human rights body observed that the allegations made therein prima facie appear to involve violations of the human rights of the victims.

Accordingly, the NHRC directed the Home Secretary and the DGP, Uttar Pradesh, to submit a detailed Action Taken Report within the stipulated period for its consideration. It also directed that a copy of the proceedings be forwarded to the Uttar Pradesh Chief Secretary to ensure necessary compliance in the matter.

--IANS

Source: <https://globalgovernancenews.com/nhrc-reviews-86-bonded-labour-cases-in-haryana/>

HomeGOVERNANCE NEWSNHRC Reviews 86 Bonded Labour Cases in Haryana

NHRC Reviews 86 Bonded Labour Cases in Haryana

Justice V. Ramasubramanian calls for labour helpline and stricter implementation of bonded labour laws
By Global Governance News On Jul 10, 2026

GG News Bureau

New Delhi, 10th July: The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday conducted an online hearing of 86 cases of alleged bonded labour in brick kilns across various districts of Haryana, stressing the need for stronger enforcement mechanisms and better protection of vulnerable workers.

The hearing was chaired by NHRC Chairperson Justice V. Ramasubramanian in the presence of Joint Secretary Samir Kumar, Joint Registrar (Law) Indrajeet Kumar and other senior officials. Senior functionaries of the Haryana government, including Chief Secretary Anurag Rastogi, Labour Commissioner Vijaykumar Bhavikatti and District Magistrates from all districts, also participated.

Justice Ramasubramanian observed that records in many cases had not been properly examined by the concerned authorities, making it difficult to establish credible evidence for declaring labourers as bonded labourers. He urged officials to remain vigilant while handling such cases and strictly follow the Standard Operating Procedure for Identification and Rescue of Bonded Labourers and Prosecution of Offenders, issued by the Ministry of Labour and Employment on May 14, 2026.

Highlighting the need for stronger monitoring, the NHRC Chairperson proposed launching a dedicated helpline for labourers along with maintaining proper employment records to help track and address incidents of bonded labour more effectively.

During the hearing, NHRC Joint Secretary Samir Kumar stressed the importance of implementing the Commission's directions and acting in accordance with its 'Advisory 2.0 to Identify, Release and Rehabilitate Bonded Labourers.' The Commission also reviewed Action Taken Reports submitted by District Magistrates on the complaints under consideration.

The Haryana Chief Secretary and Labour Commissioner assured the Commission that all 86 cases would be reviewed thoroughly and the required reports submitted. They also committed to ensuring full compliance with the directions of the Supreme Court and applicable laws to facilitate prompt action in bonded labour cases.

Source: <https://theprint.in/india/nhrc-issues-notice-to-up-home-secy-dgp-over-unprovoked-lathi-charge-on-protesters-in-meerut/2983018/>

HomeIndiaNHRC issues notice to UP home secy, DGP over 'unprovoked' lathi-charge on...

India

NHRC issues notice to UP home secy, DGP over 'unprovoked' lathi-charge on protesters in Meerut
PTI 10 July, 2026 03:50 pm IST

New Delhi, Jul 10 (PTI) The NHRC has issued a notice to the Uttar Pradesh DGP and the state's home secretary in the wake of a complaint alleging that police resorted to "unprovoked, brutal lathi-charge" during a "peaceful" public demonstration in Meerut, inflicting severe injuries on multiple protesters, according to the proceedings of the case.

The allegations made in the complaint prima facie seem to be violations of the victims' human rights, it said, adding the National Human Rights Commission (NHRC) has sought an action taken report within 15 days.

An NHRC bench presided by its member Priyank Kanoongo took cognisance of the case under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, according to the proceedings dated July 10.

The complainant, Sunil Ahirwar of Bhopal, alleged that "during a peaceful public demonstration in Meerut demanding justice in the Lalita Gautam murder case, police unleashed an unprovoked, brutal lathi-charge, inflicting severe physical injuries on multiple protesters".

The complainant also alleged that widely circulated videos depicted senior police officers "committing custodial torture by mercilessly beating defenceless individuals", who had already been taken into custody, demonstrating a "complete breakdown" of rule of law and structural violation of personal dignity, the proceedings said.

The complainant sought immediate intervention by the NHRC to register a complaint, and demanded that the chief secretary and the DGP submit a comprehensive report, initiate an independent inquiry into the case, and verify the viral videos to establish individual accountability, provide immediate medical rehabilitation and statutory financial compensation to all the injured, and order swift criminal and disciplinary action against the "defaulting police officers", the proceedings said.

The registry is directed to issue a notice to the home secretary of Uttar Pradesh, and its DGP, to submit an action taken report within 15 days for perusal of the Commission, they added.

A copy of the proceedings is to be transmitted to the chief secretary to ensure necessary compliance in the matter, the proceedings said. PTI KIND ARI

Source: <https://thechenabtimes.com/2026/07/10/uttar-pradesh-nhrc-issues-notice-to-dgp-home-secretary-over-alleged-police-excess-in-meerut-protest/?amp=1>

Uttar Pradesh: NHRC Issues Notice to DGP, Home Secretary Over Alleged Police Excess in Meerut Protest
News Desk CT 3 hours ago

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Director General of Police (DGP) and the Home Secretary of Uttar Pradesh following allegations of police excess during a protest in Meerut. The notices were issued based on a complaint detailing an alleged unprovoked and brutal lathi-charge on demonstrators.

Information was available with The Chenab Times indicating that the complaint lodged with the NHRC asserted that the police action resulted in severe injuries to several protesters. The demonstration, described as a peaceful public gathering, was reportedly organised to demand justice in the murder case of a Dalit woman.

The commission, in its notice, has sought a report from the state authorities within four weeks. This report is expected to provide details regarding the circumstances of the alleged lathi-charge and the measures taken by the police. The NHRC's intervention underscores the seriousness of the allegations and the importance of ensuring that law enforcement actions adhere to human rights standards, particularly during peaceful protests.

The incident allegedly occurred during a protest where participants were demanding justice for a victim. According to the complaint filed with the NHRC, the police response was disproportionate to the situation, leading to significant harm to individuals who were part of a peaceful assembly. The nature of the injuries sustained by the protesters has been highlighted as a key concern in the complaint.

The NHRC, a statutory body established under the Protection of Human Rights Act, 1993, plays a crucial role in protecting and promoting human rights in India. It has the power to investigate complaints of human rights violations, either on its own initiative or upon receiving a petition from any person. Its directives often carry significant weight, prompting state governments to address issues of concern promptly.

The Uttar Pradesh Police force, like any other state police department, operates under strict guidelines regarding the use of force. However, allegations of police brutality can arise, and such complaints are typically subject to internal inquiries and, in more serious cases, external oversight by bodies like the NHRC. The commission's notices are a procedural step aimed at gathering factual information to ascertain the veracity of the claims.

The context of the protest itself—demanding justice for a Dalit woman—also brings into focus issues of social justice and the protection of vulnerable communities. Protests and demonstrations are constitutionally protected forms of expression, and any alleged undue force used by law enforcement agencies during such events is a matter of grave concern for human rights advocates and the judiciary.

The NHRC's standard operating procedure in such cases involves seeking a response from the implicated authorities. This response is then reviewed by the commission to determine if further action is warranted, which could include recommending compensation for victims, initiating disciplinary proceedings against erring officials, or suggesting policy changes to prevent future occurrences. The issuance of notices to the highest police and

home department officials indicates the gravity with which the commission views the complaint.

The Meerut district, located in the western part of Uttar Pradesh, has been the site of various social and political activities. Police conduct during public gatherings and protests has been a subject of scrutiny in different parts of the country, and the NHRC's involvement in this case serves as a reminder of the accountability mechanisms in place.

The Home Secretary, as the administrative head of the department responsible for internal security and law and order, and the DGP, as the head of the state police force, are the appropriate authorities to respond to such allegations. Their prompt attention and a comprehensive report are expected to shed light on the incident and pave the way for appropriate resolution.

Source: <https://www.telegraphindia.com/india/congress-targets-bjps-anti-dalit-face-over-meerut-murder-nhrc-issues-notice-on-unprovoked-lathi-charge/cid/2169483>

Congress targets BJP's 'anti-Dalit' face over Meerut murder; NHRC issues notice on 'unprovoked' lathi-charge

Citing NCRB data, the Congress chief said that between 2013 and 2024, crimes against women in the country have increased by nearly 42.6 per cent, and crimes against Scheduled Castes by nearly 41 per cent

PTI Published 10.07.26, 04:28 PM

Attacking the BJP over the murder of a woman in Meerut, Congress chief Mallikarjun Kharge on Friday said it has exposed the "anti-Dalit" face of that party's double-engine government and asserted that the rising tide of the voice of Dalits and the oppressed will soon uproot the ruling regime's "throne of power".

The Congress president's remarks came after seven people were arrested and more than 30 others booked for unlawful assembly and attacking police personnel, among other charges, in connection with a protest over the woman's murder.

According to police, Lalita Gautam went missing from the T P Nagar area in Meerut on May 15 and was found dead in the Rohta area on May 17. The main accused was arrested on May 18 and another accused was arrested later for allegedly destroying evidence. Police said the investigation had since revealed the role of more people.

Of those booked, more than 25 are unidentified, they said.

In a post in Hindi on X, Kharge said the brutal murder of the Dalit student from Meerut has once again exposed the "anti-woman and anti-Dalit face" of the BJP's double-engine government.

"The victim's family is pleading for justice, but instead of listening to their voice, the government is busy crushing those demanding justice," Kharge said.

Citing NCRB data, the Congress chief said that between 2013 and 2024, crimes against women in the country have increased by nearly 42.6 per cent, and crimes against Scheduled Castes by nearly 41 per cent.

In the country, every two hours and three minutes, a Scheduled Caste (SC) woman is raped, meaning 12 cases of rape of Dalit women are registered everyday, he claimed.

"These are not just statistics; they are proof of the growing insecurity of women, Dalits, and the deprived under the BJP rule. When Congress leaders arrive to stand with the victim's family, they are arrested, placed under house arrest, and stopped with batons. What truth is the Yogi government trying to hide, after all? Why is the opposition being prevented from meeting the family? Why is there police repression instead of listening to the family and delivering justice?" Kharge said.

The country had also seen in Hathras and Unnao, how the BJP government suppressed the victims' voices and

tried to protect those connected with power, he said.

"Now, the same repressive attitude is being repeated in Meerut. The victim's family needs justice, not batons and house arrests. The culprits must receive the harshest punishment, and the suppression of the voice of the victim's family must stop immediately!" he said.

"Remember... the rising tide of the voice of Dalits, the deprived, and the oppressed will soon uproot the BJP's throne of power," Kharge said in his post.

Protesters gathered at the commissioner's crossing in Meerut on Wednesday to protest the murder of the woman.

The victim's family has been kept informed about the developments in the case throughout. Some people instigated the family and organised the blockade outside the Collectorate on the pretext of submitting a memorandum, police said.

The protesters had gathered without permission and blocked a key road. They attempted to force their way into the district magistrate's office after breaking the main gate and assaulted police and administrative officials despite repeated requests to disperse. Eleven policemen were injured in the incident, they said.

One of the organisers threatened self-immolation to pressure the police personnel, they said.

The NHRC has issued a notice to the Uttar Pradesh DGP and the state's home secretary in the wake of a complaint alleging that police resorted to "unprovoked, brutal lathi-charge" during a "peaceful" public demonstration in Meerut, inflicting severe injuries on multiple protesters, according to the proceedings of the case.

The allegations made in the complaint prima facie seem to be violations of the victims' human rights, it said, adding the National Human Rights Commission (NHRC) has sought an action taken report within 15 days.

The complainant, Sunil Ahirwar of Bhopal, alleged that "during a peaceful public demonstration in Meerut demanding justice in the Lalita Gautam murder case, police unleashed an unprovoked, brutal lathi-charge, inflicting severe physical injuries on multiple protesters".

The complainant also alleged that widely circulated videos depicted senior police officers "committing custodial torture by mercilessly beating defenceless individuals", who had already been taken into custody, demonstrating a "complete breakdown" of rule of law and structural violation of personal dignity, the proceedings said.

The complainant sought immediate intervention by the NHRC to register a complaint, and demanded that the chief secretary and the DGP submit a comprehensive report, initiate an independent inquiry into the case, and verify the viral videos to establish individual accountability, provide immediate medical rehabilitation and statutory financial compensation to all the injured, and order swift criminal and disciplinary action against the "defaulting police officers", the proceedings said.

Source: <https://indtoday.com/nhrc-reviews-86-alleged-bonded-labour-cases-in-haryana-brick-kilns-seeks-stronger-action/>

HomeIndiaNHRC Reviews 86 Alleged Bonded Labour Cases In Haryana Brick Kilns, Seeks...

IndiaTop Stories

NHRC Reviews 86 Alleged Bonded Labour Cases In Haryana Brick Kilns, Seeks Stronger Action

By IND Today News Desk July 10, 2026

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday conducted an online hearing into 86 cases of alleged bonded labour in brick kilns across various districts of Haryana, stressing the need for stricter implementation of laws, better investigations, and stronger mechanisms to identify and rescue bonded labourers.

The hearing was chaired by NHRC Chairperson Justice V. Ramasubramanian in the presence of Joint Secretary Samir Kumar, Joint Registrar (Law) Indrajeet Kumar, and other senior officials. Senior Haryana government officials, including Chief Secretary Anurag Rastogi, Labour Commissioner Vijaykumar Bhavikatti, and District Magistrates from across the state, also participated.

NHRC Flags Gaps in Investigations

During the hearing, Justice Ramasubramanian observed that records in many cases had not been examined thoroughly, resulting in a lack of credible evidence to declare affected workers as bonded labourers.

He urged officials to remain vigilant while handling such complaints and directed them to strictly follow the Standard Operating Procedure (SOP) for Identification and Rescue of Bonded Labourers and Prosecution of Offenders, issued by the Ministry of Labour and Employment on May 14, 2026, while constituting inquiry teams.

The NHRC Chairperson also recommended launching a dedicated helpline to enable labourers to seek assistance and facilitate timely reporting and tracking of bonded labour cases.

NHRC Calls for Full Compliance

NHRC Joint Secretary Samir Kumar emphasised the importance of implementing the Commission's directions and acting in accordance with its "Advisory 2.0 to Identify, Release and Rehabilitate Bonded Labourers."

The Commission reviewed the Action Taken Reports (ATRs) submitted by District Magistrates regarding the complaints under consideration.

During the proceedings, Chief Secretary Anurag Rastogi and Labour Commissioner Vijaykumar Bhavikatti assured the Commission that all 86 cases would be reviewed afresh and that the required reports would be submitted.

The state government also assured the NHRC that it would ensure full compliance with Supreme Court directions

and all applicable laws to facilitate prompt identification, rescue, rehabilitation, and legal action in bonded labour cases.

Source: <https://www.thestatesman.com/india/nhrc-seeks-report-from-up-dgp-home-secretary-on-police-lathi-charge-in-meerut-1503615176.html/amp>

NHRC seeks report from UP DGP, Home Secretary on police lathi-charge in Meerut
Statesman News Service July 10, 2026 6:57 pm

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of a complaint submitted by the Dr Ambedkar Jan Kalyan Samiti, alleging serious human rights violations during a peaceful public demonstration in Meerut, Uttar Pradesh.

According to the complaint, the demonstration was organised to demand justice in a murder case. It has been alleged that the local police resorted to an unprovoked and brutal lathi-charge on the peaceful protesters, leaving several participants with serious injuries.

Taking note of the seriousness of the allegations concerning the use of force against peaceful demonstrators and the possible violation of their human rights, the NHRC Bench, headed by Member Priyank Kanoongo, has issued notices to the Director General of Police, Uttar Pradesh, and the Principal Secretary (Home), Government of Uttar Pradesh, seeking a detailed report on the incident.

The Commission has sought information regarding the circumstances that led to the use of force, the injuries sustained by the protesters, the justification for the police action, the medical assistance provided to the injured, and the steps taken to ensure accountability if any excesses are found.

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/protest-over-dalit-student-murder-nhrc-seeks-report-from-up-dgp-home-secy-as-meerut-turns-into-fortress/amp_articleshow/132317423.cms

Protest over Dalit student murder: NHRC seeks report from UP DGP, home secy as Meerut turns into fortress City | Jul 10, 2026, 22:52 IST

Meerut: Two days after alleged police high-handedness on protesting members of the Dalit community over a case involving the killing of a college student -- Lalita Gautam, the National Human Rights Commission (NHRC) on Friday sought a detailed action-taken report from the UP DGP and the home secretary within 15 days. Police action also kicked up a political storm, evoking response from Opposition parties, prompting cops to turn Meerut into a fortress as a "precautionary step" and "sealing off" the student's village.

In the letter, accessed by TOI, NHRC bench has asked the UP top brass to furnish a report in reply to allegations by complainant Sunil Ahirwar of Jan Kalyan Samiti that, "police (Meerut) unleashed an unprovoked, brutal baton-charge inflicting severe injuries on many protesters."

The letter added that, "there is also video evidence that clearly depicts senior police officers committing custodial torture by mercilessly beating defenceless individuals while they were already in custody." Ahirwar of Bhopal filed the complaint under section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

On Thursday, police registered a case against 63 protesters under stringent BNS sections of "attempt to murder" and "assault on women with an intention to outrage modesty" for the alleged assault on female police personnel. Seven of them were later arrested.

The thrashing of a Noida-based lawyer -- Ravi Gautam -- inside a police van on Wednesday also did not go down well within the advocate fraternity. Angry lawyers from the Meerut Bar Association submitted a memorandum at the Collectorate.

Meanwhile, SSP Avinash Pandey issued a fresh statement: "Our Constitution starts with — We the People of India. It does not start with caste, creed or any community. Whatever action was taken, it was against criminals and we have justification of all the actions along with the proof."

Reacting to an alleged audio threat, SSP Pandey appealed to all his "supporters and opposers to plant trees in the forthcoming 'Vriksharopan Mahotsav' (plantation drive)... They must use their anger and energy on the betterment of the environment and society."

From early Friday, heavy police force was deployed at the city's Commissioner's Park, the protest venue. It was personally supervised by SSP Pandey.

The district's borders were sealed and the political leaders, including MP from Nagina Lok Sabha constituency, Chandrashekhar Azad, were stopped at the outskirts along with hundreds of his supporters. Addressing the public, Azad said, "If the Constitution has given the citizens the right to protest, then which are the sections under which the peaceful agitators were attacked, I want to know. I have come to Meerut to get the answer and also to

meet the victim's family."

Poonam Pandit, a Congress functionary, was allegedly detained at her house in Bulandshahr in the early hours of Friday. She was scheduled to meet the student's family. She asked: "Is it a crime to meet the aggrieved family, to share their grief? The best answer to why I have been put under house arrest lies with the state govt."

Notably, people from the community, including various outfits, had joined Lalita's parents in regular protests against the "shoddy probe" by local police after the body of the 20-year-old BA final-year student from Meerut was found in a sugarcane field. The Dalit student went missing on May 15, 2026, after leaving her home for an exam.

Police arrested her alleged boyfriend, Ankush Kumar, claiming he killed her following an argument. However, her family questioned the police investigation, demanding a fair and comprehensive probe into the case.

Source: <https://thenewsmill.com/2026/07/nhrc-india-reviews-86-alleged-bonded-labour-cases-in-haryana-brick-kilns/>

Nation and Beyond

NHRC India reviews 86 alleged bonded labour cases in Haryana brick kilns

TNM (With ANI Inputs) Published On: Jul 10, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC) of India conducted an online hearing of 86 alleged bonded labour cases from brick kilns across various districts in Haryana.

Justice V Ramasubramanian, Chairperson of the NHRC, presided over the hearing, which was attended by Joint Secretary Samir Kumar, Joint Registrar (Law) Indrajeet Kumar, and other senior officials. Senior representatives of the Haryana state government, including Chief Secretary Anurag Rastogi, Labour Commissioner Vijaykumar Bhavikatti, and the District Magistrates of all districts, were also present.

Justice Ramasubramanian remarked that in most cases, government officials had not properly examined records and therefore lacked credible evidence to classify the labourers as bonded labourers. He urged officers to exercise greater vigilance when handling bonded labour cases and to adhere to the Standard Operating Procedure for Identification and Rescue of Bonded Labourers and Prosecution of Offenders, issued by the Ministry of Labour and Employment on May 14. He also emphasised the importance of establishing a helpline to enable labourers to seek assistance and aid in tracking bonded labour incidents.

Joint Secretary Samir Kumar highlighted the need for compliance with NHRC directives and implementation of its 'Advisory 2.0 to Identify, Release and Rehabilitate Bonded Labourers.' The Chief Secretary, Labour Commissioner, and District Magistrates presented the cases during the hearing, and the Commission reviewed the Action Taken Reports submitted by the District Magistrates on the complaints.

The Chief Secretary and Labour Commissioner assured the Commission that all 86 cases would be thoroughly reviewed and that necessary information and reports would be submitted subsequently. They also committed to ensuring full compliance with Supreme Court directions and applicable laws to enable prompt remedial action in bonded labour cases.

Source: <https://www.thehindu.com/news/national/uttar-pradesh/nhrc-issues-notice-to-up-dgp-home-secretary-over-alleged-police-excess-during-meerut-protest/article71206347.ece/amp/>

NHRC issues notice to U.P. DGP, Home Secretary over alleged police excess during Meerut protest

Complaint with NHRC says police carried out an 'unprovoked, brutal lathi-charge' on participants in what was described as a peaceful public demonstration demanding justice in the murder case of a Dalit woman, that left several protesters with severe injuries

Published - July 10, 2026 07:19 pm IST - New Delhi
The Hindu Bureau

The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday (July 10, 2026) issued notices to the Uttar Pradesh Director General of Police (DGP) and the State Home Secretary over allegations that police used excessive force against protesters during a demonstration in Meerut held on July 8 demanding justice in the murder case of a Dalit woman.

The notice was issued after an NHRC Bench headed by member Priyank Kanoongo took cognisance of a complaint filed by Sunil Ahirwar of Bhopal under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

Report in 15 days

The Commission directed the U.P Home Secretary and the DGP to submit an action taken report within 15 days for its consideration.

According to the complaint, police carried out an "unprovoked, brutal lathi-charge" on participants in what was described as a peaceful public demonstration, that left several protesters with severe injuries.

It further alleged that videos widely circulated on social media appeared to show senior police officers assaulting individuals who had already been taken into custody. The complaint claimed that such actions amounted to custodial torture and reflected a breakdown of the rule of law as well as a violation of personal dignity.

Seek independent probe

The complainant sought an independent inquiry into the incident, verification of viral videos to establish individual accountability, immediate medical treatment and rehabilitation for those injured, financial compensation for the victims, and criminal as well as departmental action against police personnel found responsible.

The protest was held in connection with the alleged murder of Lalita Gautam, a 20-year-old BA final-year student from Meerut. She went missing on May 15 after leaving home to attend college, and her body was later found in a sugarcane field. Police arrested her alleged boyfriend, Ankush Kumar, claiming he killed her following an argument, and later arrested another person for allegedly helping destroy evidence. However, her family questioned the police investigation, demanded the arrest of all those involved, and sought a fair and comprehensive probe into the case.

Source: <https://nhrc.nic.in/media/press-release/nhrc,-india-hears-online-86-cases-of-alleged-bonded-labour-in-haryana-brick-kilns>

Home Media Press Release NHRC, India hears online 86 cases of all..

NHRC, India hears online 86 cases of alleged bonded labour in Haryana brick kilns
Press release

National Human Rights Commission

New Delhi: 10th July, 2026

NHRC, India hears online 86 cases of alleged bonded labour in Haryana brick kilns

Chairperson, Justice V. Ramasubramanian highlights the need for a helpline for labourers with a proper record of their employment to help track incidents of bonded labour

Submission of reports in all the cases as per the directions of the NHRC assured by the state

Authorities assure compliance with Supreme Court directives and laws to address cases of bonded labour

The National Human Rights Commission (NHRC), India heard 86 cases online of alleged bonded labour in brick kilns across various districts of Haryana. Chairperson, Justice V. Ramasubramanian presided over the hearing in the presence of Joint Secretary, Shri Samir Kumar, Joint Registrar (Law), Shri Indrajeet Kumar and other senior officers. The hearing was attended by senior functionaries of the state government, including the Chief Secretary, Shri Anurag Rastogi, Labour Commissioner, Shri Vijaykumar Bhavikatti and the District Magistrates (DMs) of all the districts.

Justice Ramasubramanian said that in most of the cases, the records had not been properly examined by the concerned government functionaries. Therefore, they did not have credible evidence to declare the labourers as bonded labourers. He urged the officers to remain vigilant while dealing with cases of bonded labour. He further asked them to follow the requirements laid down in the Standard Operating Procedure for Identification and Rescue of Bonded Labourers and Prosecution of Offenders, issued by the Ministry of Labour and Employment vide letter dated 14th May 2026, while constituting the team for the enquiry into the complaint. He also emphasised the need to launch a helpline so that labourers can seek help when needed to help track the incidents of bonded labour.

Shri Samir Kumar, Joint Secretary, NHRC highlighted the need to comply with the NHRC directions and take action as per its 'Advisory 2.0 to Identify, Release and Rehabilitate Bonded Labourers.' The Haryana Chief Secretary, the Labour Commissioner and the DMs presented the bonded labour cases during the hearing. The Commission reviewed the Action Taken Reports (ATRs) submitted by the DMs on the complaints under its consideration.

The Chief Secretary and the Labour Commissioner assured the Commission that all the 86 cases would be reviewed and the requisite information and reports would be submitted thereafter. They also assured the

Commission that full compliance with the directions of the Supreme Court and the applicable laws would be ensured to facilitate immediate remedial action in cases relating to bonded labour.

Source: <https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/meerut-lalita-gautam-murder-case-human-rights-commission-registers-case-regarding-the-slap-incident-201783705514778.amp.html>

ललिता गौतम हत्याकांड: थप्पड़ कांड में मानवाधिकार आयोग ने दर्ज किए केस, डीजीपी से मांगा जवाब
Jul 10, 2026 11:29 pm IST By Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान

Meerut Lalita Gautam Murder Case: मेरठ के थप्पड़ कांड और लाठीचार्ज के मामले में रिटायर्ड आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की ओर से राज्य मानवाधिकार आयोग को भेजी शिकायत पर केस दर्ज किया गया है।

Meerut Lalita Gautam Murder Case: मेरठ के थप्पड़ कांड और लाठीचार्ज का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर गरमा गया है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रिटायर्ड आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की ओर से राज्य मानवाधिकार आयोग को भेजी शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। दूसरी ओर, भोपाल के डॉ. अंबेडकर जनकल्याण समिति की ओर से भेजी गई शिकायत का भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर लिया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, साथ ही टिप्पणी भी की है कि मौजूद वीडियो आधार पर यह प्रकरण प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों के उल्लंघन का पाया गया है।

रोहटा के थिरोट गांव निवासी ललिता गौतम की हत्या के मामले में बाकी आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर 8 जुलाई को मेरठ कमिश्नरी पर धरने के दौरान पुलिस ने लाठियां फटकारी थीं और एसएसपी ने लोगों पर थप्पड़ बरसाए थे। बंदी वाहन में बंद एक आरोपी रवि गौतम को एसएसपी द्वारा पीटने का वीडियो भी वायरल हुआ था।

रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने मारपीट, थप्पड़बाजी और लाठीचार्ज की तमाम वीडियो के साथ शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग में की थी। राज्य मानव अधिकार आयोग ने इसे लेकर केस संख्या 14615/24/54/2026 दर्ज कर लिया है। अमिताभ ठाकुर ने शिकायत में कहा था कि एसएसपी मेरठ द्वारा मारपीट किया जाना गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और जवाबदेही का विषय है।

डॉ. अंबेडकर जनकल्याण समिति की शिकायत पर भी केस

लाठीचार्ज और थप्पड़ कांड को लेकर भोपाल की डॉ. अंबेडकर जनकल्याण समिति ने भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी थी। वीडियो साक्ष्य भी शिकायत के साथ भेजे गए थे। इस पर आयोग ने केस संख्या 7581/24/54/2026 दर्ज कर लिया है, साथ ही यूपी के डीजीपी और सचिव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि प्रथम दृष्टया शिकायत के साथ जो वीडियो साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनके अनुसार मानवाधिकारों के उल्लंघन का प्रकरण पाया गया है। 15 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है।

Source: <https://hindi.theprint.in/india/helpline-will-help-victims-of-bonded-labour-human-rights-commission-chief/997690/?amp>

होम देश हेल्पलाइन से बंधुआ मजदूरी के पीड़ितों को मिल सकेगी मदद: मानवाधिकार आयोग...

देश

हेल्पलाइन से बंधुआ मजदूरी के पीड़ितों को मिल सकेगी मदद: मानवाधिकार आयोग प्रमुख

भाषा- 10 July, 2026

नयी दिल्ली, 10 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी. रामासुब्रमण्यम ने अधिकारियों से बंधुआ मजदूरी के मामलों से निपटते समय सतर्क रहने का आग्रह किया है।

उन्होंने इस तरह के मामलों का पता लगाने और जरूरत पड़ने पर मजदूरों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए हेल्पलाइन शुरू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

एनएचआरसी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि आयोग ने नौ जुलाई को हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईट-भट्टों से जुड़े कथित बंधुआ मजदूरी के 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यम की अध्यक्षता में हुई इस सुनवाई में राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों और हरियाणा के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

उन्होंने कहा कि अधिकांश मामलों में अभिलेखों की "समुचित पड़ताल संबंधित सरकारी अधिकारियों ने नहीं की।" आयोग ने एक बयान में कहा, "इस कारण उनके पास मजदूरों को बंधुआ मजदूर घोषित करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य नहीं थे।"

आयोग के प्रमुख ने अधिकारियों से बंधुआ मजदूरी के मामलों से निपटते समय सतर्क रहने का आग्रह किया।

उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि किसी शिकायत की जांच के लिए टीम गठित करते समय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 14 मई को जारी पत्र के माध्यम से जारी 'बंधुआ मजदूरों की पहचान और बचाव तथा दोषियों के अभियोजन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया' में निर्धारित प्रावधानों का पालन करें।

उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया कि एक हेल्पलाइन शुरू की जानी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर मजदूर सहायता मांग सकें और बंधुआ मजदूरी की घटनाओं का पता लगाने में मदद मिल सके।

एनएचआरसी के संयुक्त सचिव समीर कुमार ने आयोग के निर्देशों का पालन करने और 'बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास के लिए परामर्श 2.0' के अनुरूप कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया।

बयान में कहा गया कि सुनवाई के दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव, श्रम आयुक्त और जिलाधिकारियों ने बंधुआ मजदूरी के मामलों का ब्योरा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया। आयोग ने विचाराधीन शिकायतों पर जिलाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा भी की।

बयान के अनुसार, राज्य के मुख्य सचिव और श्रम आयुक्त ने आयोग को आश्वासन दिया कि सभी 86 मामलों की "समीक्षा" की जाएगी और इसके बाद आवश्यक जानकारी एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इसके अनुसार उन्होंने आयोग को यह भी आश्वासन दिया कि बंधुआ मजदूरी से जुड़े मामलों में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और लागू कानूनों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

भाषा अमित माधव

Source: [https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?](https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2283250®=3&lang=2)

[PRID=2283250®=3&lang=2](https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2283250®=3&lang=2)

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हरियाणा के ईट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी के 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की

एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन ने बंधुआ मजदूरी की घटनाओं पर नज़र रखने और श्रमिकों की सहायता हेतु एक हेल्पलाइन की जरूरत पर बल दिया, जिसमें उनके रोजगार संबंधी रिकॉर्ड हो

राज्य ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के निर्देशों के अनुसार सभी मामलों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया

अधिकारियों ने बंधुआ मजदूरी के मामले निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किया
प्रविष्टि तिथि: 10 JUL 2026 12:53PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी के 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की। एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन ने संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार, संयुक्त रजिस्ट्रार (कानून) श्री इंद्रजीत कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सुनवाई की अध्यक्षता की। सुनवाई में हरियाणा सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, श्रम आयुक्त श्री विजयकुमार भाविकट्टी और सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) शामिल थे।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमणियन ने कहा कि अधिकतर मामलों में संबंधित सरकारी अधिकारियों ने अभिलेखों की ठीक से जांच नहीं की थी। इसलिए, उनके पास श्रमिकों को बंधुआ मजदूर घोषित करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य नहीं थे। उन्होंने अधिकारियों से बंधुआ मजदूरी के मामलों से निपटते समय सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत की जांच के लिए टीम का गठन करते समय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 मई 2026 को जारी बंधुआ मजदूरों की पहचान और बचाव तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन किया जाए। उन्होंने बंधुआ मजदूरी की घटनाओं पर नज़र रखने में मदद के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करने की जरूरत पर भी बल दिया ताकि श्रमिक जरूरत पड़ने पर सहायता प्राप्त कर सकें।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार ने एनएचआरसी के निर्देशों का पालन करने और 'बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास हेतु जारी सलाह 2.0' के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया। सुनवाई के दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव, श्रम आयुक्त और जिला प्रशासकों ने बंधुआ मजदूरी के मामले प्रस्तुत किए। आयोग ने अपने समक्ष विचाराधीन शिकायतों पर जिला प्रशासकों की जमा की गई कार्रवाई रिपोर्टों (एटीआर) की समीक्षा की।

मुख्य सचिव और श्रम आयुक्त ने मानवाधिकार आयोग को आश्वासन दिया कि सभी 86 मामलों की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद आवश्यक जानकारी और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने एनएचआरसी को यह भी आश्वासन दिया कि बंधुआ मजदूरी से संबंधित मामलों में तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और लागू कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

पीके/केसी/एके/एमपी

Source: <https://www.deshbandhu.co.in/featured-news/meerut-lathi-charge-case-nhrc-seeks-report-from-up-dgp-home-secretary-309172>

मेरठ लाठीचार्ज मामले में NHRC सख्त, यूपी DGP और गृह सचिव से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस लाठीचार्ज और हिरासत में मारपीट के मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और गृह सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है।

By - Deshbandhu Desk 10 July 2026 1:24 PM

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस लाठीचार्ज और हिरासत में मारपीट के मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और गृह सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है। यह कार्रवाई प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायत डॉ. अंबेडकर जन कल्याण समिति, भोपाल की ओर से आयोग को भेजी गई थी। शिकायत पर विचार करने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर आयोजित शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान स्थानीय पुलिस ने बिना किसी उकसावे के प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। आरोप है कि इस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर शारीरिक चोटें आईं। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हिरासत में लिए गए निहत्थे लोगों की बेरहमी से पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

शिकायत में आयोग से मांग की गई कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कर संबंधित पुलिस अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाए। इसके अलावा घायल प्रदर्शनकारियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा, पुनर्वास और कानून के अनुसार आर्थिक मुआवजा देने की भी मांग की गई है। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई करने की भी अपील की गई है। एनएचआरसी ने आदेश में कहा है कि शिकायत में लगाए गए आरोप पहली नजर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला प्रतीत होते हैं। इसी आधार पर आयोग ने उत्तर प्रदेश के गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी इस मामले की प्रति भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि मामले से संबंधित रिपोर्ट आयोग को ई-मेल के माध्यम से भी भेजी जाए।

Source: <https://hindi.dynamitenews.com/uttar-pradesh/up-police-dgp-nhrc-notice-meerut-lalita-gautam-murder-ase-controversy>

हिंदी न्यूज़>उत्तर प्रदेश न्यूज़>मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड में UP Police की किरकिरी; UP DGP को नोटिस; जानिये केस में बड़े अपडेट

मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड में UP Police की किरकिरी; UP DGP को नोटिस; जानिये केस में बड़े अपडेट

उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर राज्य की सियासत गरमा गई है। इस मामले में यूपी पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब यूपी डीजीपी को इस केस में नोटिस जारी किया गया है।

Post Published By: सौम्या सिंह

Updated : 10 July 2026, 1:18 PM IST

Meerut/Lucknow: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड का मामला अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। मेरठ से लेकर दिल्ली और लखनऊ तक यह मामला गरमाता जा रहा है। ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर अब विरोध-प्रदर्शन तेज हो गये हैं। इस केस में अब यूपी पुलिस और मेरठ के एसएसपी की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

ललिता गौतम हत्याकांड में अब नया मोड़ आ गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने अब उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी किया है। NHRC ने DGP को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

दरअसल, पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर गुस्साये दलित समाज के लोगों पर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाने की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की थी। अमिताभ ठाकुर की इसी शिकायत पर NHRC ने डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दखल के बाद अब इस मामले ने पूरी तरह तूल पकड़ लिया है। आयोग ने यूपी डीजीपी को भेजे नोटिस में पुलिसिया कार्रवाई पर कड़े सवाल उठाए हैं और पूछा है कि प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करने की नौबत क्यों आई? इसके साथ ही, आयोग ने पीड़ित परिवार को दी गई सुरक्षा और अब तक की गई कानूनी कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। इस नोटिस के बाद मेरठ पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया है और मामले की लीपापोती में जुटे अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

राजनीतिक गलियारों में भी इस घटना को लेकर उबाल है। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और अन्य दलित संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि ललिता गौतम के हत्यारों को जल्द से जल्द सख्त सजा नहीं मिली और लाठीचार्ज करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे। भीम आर्मी के प्रमुख ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है।

फिलहाल, लखनऊ मुख्यालय से मिली गाइडलाइंस के बाद मेरठ एसएसपी ने मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम (SIT) का गठन कर दिया है। पुलिस अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।

Source: <https://royalbulletin.in/national/nhrc-strict-on-bonded-labor-in-brick-kilns-of-haryana/article-198524>

हरियाणा के ईट भट्टों में बंधुआ मजदूरी पर एनएचआरसी सख्त, 86 मामलों पर की ऑनलाइन सुनवाई, रिकॉर्ड की जांच को लेकर अधिकारियों को फटकार

मुख्य सचिव और श्रम आयुक्त को हर केस की समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

By ओ.पी. पाल। स्वतंत्र पत्रकार

Jul 10, 2026 10:30 PM IST

नई दिल्ली/चंडीगढ़। हरियाणा के विभिन्न जिलों में स्थित ईट भट्टों में कथित तौर पर चल रही बंधुआ मजदूरी के 86 मामलों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन की अध्यक्षता में इन सभी 86 मामलों की एक वृहद ऑनलाइन सुनवाई की गई। इस उच्चस्तरीय सुनवाई में मानवाधिकार आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, श्रम आयुक्त श्री विजयकुमार भाविकट्टी और सूबे के सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट (DM) व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे।

दस्तावेजों की जांच में ढिलाई पर जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन ने प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अधिकतर मामलों में संबंधित सरकारी अधिकारियों ने रोजगार और श्रमिकों के अभिलेखों (रिकॉर्ड्स) की ठीक से जांच नहीं की थी, जिसके कारण उनके पास श्रमिकों को बंधुआ मजदूर घोषित करने या न करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद नहीं थे। उन्होंने सभी जिला प्रशासकों से बंधुआ मजदूरी के संवेदनशील मामलों से निपटते समय पूरी तरह सतर्क और गंभीर रहने का आग्रह किया।

नियमों का हो पालन, हेल्पलाइन शुरू करे: रामासुब्रमणियन

एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन ने शिकायत की जांच के लिए टीम का गठन करते समय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 14 मई 2026 को जारी की गई नई 'मानक संचालन प्रक्रिया' (SOP) में निर्धारित आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए। इसके साथ ही, बंधुआ मजदूरी की घटनाओं पर प्रभावी नज़र रखने और पीड़ित श्रमिकों की तत्काल सहायता व रोजगार रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू की जानी चाहिए। इसी कड़ी में एनएचआरसी के संयुक्त सचिव समीर कुमार ने भी हरियाणा सरकार को आयोग द्वारा जारी 'बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास हेतु सलाह 2.0' के अनुरूप ही त्वरित एक्शन लेने की आवश्यकता पर बल दिया।

हरियाणा सरकार ने दिया निर्देशों के अनुपालन का भरोसा

इस कड़े रुख के बाद, हरियाणा के मुख्य सचिव और श्रम आयुक्त ने मानवाधिकार आयोग को पूरी तरह आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इन सभी 86 मामलों की दोबारा से गहनता से समीक्षा करेगी और निर्धारित समय के भीतर पूरी विस्तृत रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी। उन्होंने एनएचआरसी को यह भी भरोसा दिलाया कि बंधुआ मजदूरी से संबंधित मामलों में तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए देश की सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के दिशा-निर्देशों और लागू कानूनों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

Source: <https://www.hindi.awazthevoice.in/india-news/nhrc-takes-a-tough-stance-on-the-meerut-lathi-charge-incident-seeks-a-report-from-the-up-dgp-and-home-secretary-95184.html>

मेरठ लाठीचार्ज मामले में NHRC सख्त, यूपी डीजीपी और गृह सचिव से मांगी रिपोर्ट

Story by आवाज़ द वॉयस | Published by mahashmi@awazthevoice.in | Date 10-07-2026

नई दिल्ली।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और प्रमुख सचिव (गृह) को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कार्रवाई डॉ. अंबेडकर जन कल्याण समिति की ओर से दायर शिकायत पर की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मेरठ में एक हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान स्थानीय पुलिस ने बिना किसी उकसावे के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कई लोगों को गंभीर चोटें आईं।

आयोग ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को गंभीर मानते हुए कहा कि यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ अनावश्यक बल प्रयोग किया गया है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला हो सकता है। इसी को देखते हुए एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और प्रमुख सचिव (गृह) से विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने अपने नोटिस में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी देने को कहा है। इसमें यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि आखिर किन परिस्थितियों में पुलिस ने बल प्रयोग का निर्णय लिया, प्रदर्शनकारियों को कितनी और किस प्रकार की चोटें आईं, पुलिस कार्रवाई का कानूनी आधार क्या था तथा घायल लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई या नहीं।

इसके अलावा एनएचआरसी ने यह भी पूछा है कि यदि जांच में पुलिस की ओर से किसी प्रकार की ज्यादाती या अधिकारों के दुरुपयोग की पुष्टि होती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय करने और कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

मानवाधिकार आयोग की इस कार्रवाई को मेरठ लाठीचार्ज मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग को आयोग के समक्ष पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसके आधार पर एनएचआरसी आगे की कार्रवाई तय करेगा।

Source: <https://navbharatlive.com/uttar-pradesh/meerut/meerut-lathi-charge-case-nhrc-seeks-report-from-up-government-1853612.html>

मेरठ लाठीचार्ज मामले: NHRC ने यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट, DGP और गृह सचिव को जारी किया नोटिस

Written By: दिव्या सिंह

Updated On: Jul 10, 2026 | 01:21 PM IST

सार

UP Police: मेरठ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कथित पुलिस लाठीचार्ज के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने बल प्रयोग और घायलों के इलाज पर जवाब मांगा है।

विस्तार

Meerut Lathicharge Case: यूपी के मेरठ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित लाठीचार्ज की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) और प्रमुख सचिव (गृह) को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

शिकायत के आधार पर हुई कार्रवाई

NHRC की पीठ, जिसकी अध्यक्षता सदस्य प्रियंक कानूनगो कर रहे हैं, ने डॉ. अंबेडकर जन कल्याण समिति की ओर से दायर शिकायत पर यह कार्रवाई की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मेरठ में आयोजित एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बिना किसी उकसावे के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया।

शिकायत के अनुसार, प्रदर्शन एक हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आईं, जिससे मानवाधिकारों के उल्लंघन की आशंका जताई गई है।

आयोग ने मांगे कई अहम जवाब

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि पुलिस को बल प्रयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रदर्शनकारियों को कितनी और किस प्रकार की चोटें आईं तथा कार्रवाई का कानूनी और प्रशासनिक आधार क्या था। आयोग ने यह भी जानकारी मांगी है कि घायलों को क्या चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई।

जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई का भी मांगा ब्योरा

NHRC ने अपने नोटिस में यह भी पूछा है कि यदि जांच में यूपी पुलिस की ओर से नियमों के उल्लंघन या अत्यधिक बल प्रयोग की पुष्टि होती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है या की जाएगी। आयोग ने मामले को संभावित मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा बताते हुए विस्तृत रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

Source: <https://www.bhaskarhindi.com/other/meerut-lathicharge-mamle-mein-nhrc-ne-dgp-aur-grih-sachiv-se-15-din-mein-mange-report-1326189>

Home /अन्य /मेरठ लाठीचार्ज मामले में एनएचआरसी...

मेरठ लाठीचार्ज मामले में एनएचआरसी ने यूपी के डीजीपी और गृह सचिव से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट
10 July 2026 1:12 PM

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस लाठीचार्ज और हिरासत में मारपीट के मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और गृह सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है।

नई दिल्ली, 10 जुलाई (आईएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस लाठीचार्ज और हिरासत में मारपीट के मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और गृह सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है। यह कार्रवाई प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायत डॉ. अंबेडकर जन कल्याण समिति, भोपाल की ओर से आयोग को भेजी गई थी। शिकायत पर विचार करने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर आयोजित शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान स्थानीय पुलिस ने बिना किसी उकसावे के प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। आरोप है कि इस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर शारीरिक चोटें आईं। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हिरासत में लिए गए निहत्थे लोगों की बेरहमी से पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिकायत में आयोग से मांग की गई कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कर संबंधित पुलिस अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाए। इसके अलावा घायल प्रदर्शनकारियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा, पुनर्वास और कानून के अनुसार आर्थिक मुआवजा देने की भी मांग की गई है। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक और विभागीय कार्रवाई करने की भी अपील की गई है। एनएचआरसी ने आदेश में कहा है कि शिकायत में लगाए गए आरोप पहली नजर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला प्रतीत होते हैं। इसी आधार पर आयोग ने उत्तर प्रदेश के गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी इस मामले की प्रति भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि मामले से संबंधित रिपोर्ट आयोग को ई-मेल के माध्यम से भी भेजी जाए।

Source: <https://divyakirti.com/archives/16842>

मेरठ लाठीचार्ज मामले में NHRC सख्त, यूपी DGP और गृह सचिव से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी
Divya Kirti July 10, 2026

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई पुलिस की लाठीचार्ज और हिरासत में मारपीट के मामलों को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और गृह सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से 15 दिनों के भीतर घटनाक्रम की विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) मुहैया कराने का आदेश दिया है।

यह कार्रवाई डॉ. अंबेडकर जन कल्याण समिति, भोपाल की ओर से आयोग को प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड के न्याय की मांग को लेकर किए गए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बिना किसी उकसावे प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आईं। साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गए निहत्थे लोगों की पिटाई की पुष्टि भी की गई है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ, जिसकी अध्यक्षता सदस्य प्रियंक कानूनगो कर रहे हैं, ने शिकायत को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान में लिया है। आयोग ने मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और शीघ्र जांच कराने के साथ-साथ वायरल वीडियो की सत्यता जांचने का निर्देश दिया है। जांच के बाद दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है।

शिकायत में घायल प्रदर्शनकारियों को तत्काल उचित चिकित्सा सुविधा, पुनर्वास तथा कानून के अनुसार उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रभावी आपराधिक एवं विभागीय कार्रवाई करने के लिए आयोग ने जोर दिया है।

एनएचआरसी ने प्रदेश के गृह सचिव और डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि वे 15 दिनों के भीतर पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें। इसके अलावा, इस मामले से संबंधित रिपोर्ट की एक प्रति उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी भेजी जाएगी, ताकि राज्य सरकार आवश्यक कदम उठा सके। आयोग ने रिपोर्ट सबमिशन के लिए ई-मेल के माध्यम का उपयोग करने का भी सुझाव दिया है।

यह कार्रवाई मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए की गई है, जिससे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था और जनता के बीच विश्वास बहाल किया जा सके। एनएचआरसी की इस सख्त प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति कोई भी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सरकार और पुलिस प्रशासन से उम्मीद है कि वे मामले की जांच को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पूरा करेंगे और जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होगी। इस घटना ने सुरक्षा बलों के व्यवहार और प्रदर्शनकारी अधिकारों की रक्षा पर बहस छेड़ दी है, जो सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

एनएचआरसी की इस आदेश पर मीडिया, जनप्रतिनिधि और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी निगरानी रख रहे हैं, ताकि आगे इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके और कानूनी व्यवस्था का सही ढंग से पालन हो।

इस पूरे विषय पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया आने का इंतजार किया जा रहा है।

Source: <https://insamachar.com/nhrc-conducted-an-online-hearing-regarding-86-cases-of-alleged-bonded-labour-at-brick-kilns-in-haryana/>

HomepageभारतNHRC ने हरियाणा के ईट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी के 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की

भारत

NHRC ने हरियाणा के ईट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी के 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की

Editor Posted on 10 जुलाई 2026

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी के 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की। एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन ने संयुक्त सचिव समीर कुमार, संयुक्त रजिस्ट्रार (कानून) इंद्रजीत कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सुनवाई की अध्यक्षता की। सुनवाई में हरियाणा सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, श्रम आयुक्त विजयकुमार भाविकट्टी और सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) शामिल थे।

न्यायमूर्ति रामासुब्रमणियन ने कहा कि अधिकतर मामलों में संबंधित सरकारी अधिकारियों ने अभिलेखों की ठीक से जांच नहीं की थी। इसलिए, उनके पास श्रमिकों को बंधुआ मजदूर घोषित करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य नहीं थे। उन्होंने अधिकारियों से बंधुआ मजदूरी के मामलों से निपटते समय सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत की जांच के लिए टीम का गठन करते समय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 मई 2026 को जारी बंधुआ मजदूरों की पहचान और बचाव तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन किया जाए। उन्होंने बंधुआ मजदूरी की घटनाओं पर नज़र रखने में मदद के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करने की जरूरत पर भी बल दिया ताकि श्रमिक जरूरत पड़ने पर सहायता प्राप्त कर सकें।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के संयुक्त सचिव समीर कुमार ने एनएचआरसी के निर्देशों का पालन करने और 'बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास हेतु जारी सलाह 2.0' के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया। सुनवाई के दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव, श्रम आयुक्त और जिला प्रशासकों ने बंधुआ मजदूरी के मामले प्रस्तुत किए। आयोग ने अपने समक्ष विचाराधीन शिकायतों पर जिला प्रशासकों की जमा की गई कार्रवाई रिपोर्टों (एटीआर) की समीक्षा की।

मुख्य सचिव और श्रम आयुक्त ने मानवाधिकार आयोग को आश्वासन दिया कि सभी 86 मामलों की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद आवश्यक जानकारी और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने एनएचआरसी को यह भी आश्वासन दिया कि बंधुआ मजदूरी से संबंधित मामलों में तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और लागू कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

Source: <https://www.prabhasakshi.com/national/nhrc-issues-notice-to-up-dgp-home-secretary-over-meerut-lathicharge-on-protesters>

मेरठ लाठीचार्ज मामले: मानवाधिकार आयोग ने यूपी के गृह सचिव और डीजीपी को भेजा नोटिस
प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Jul 10 2026 5:18PM

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा बिना किसी उकसावे के किए गए कथित बर्बर लाठीचार्ज को लेकर राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस गंभीर मामले में अधिकारियों से 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। यह शिकायत भोपाल निवासी सुनील अहिरवार द्वारा दर्ज कराई गई थी जिसमें पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा बिना किसी उकसावे के किए गए कथित बर्बर लाठीचार्ज मामले में कड़ा रुख अपनाया है। इस घटना में कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आने की शिकायत मिलने के बाद आयोग ने राज्य के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग के अनुसार शिकायत में लगाए गए आरोप पहली नजर में पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े प्रतीत होते हैं।

मामले की कार्यवाही के मुताबिक आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत इस शिकायत का संज्ञान लिया। 10 जुलाई को जारी इस निर्देश में आयोग के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया गया है कि वे उत्तर प्रदेश के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस भेजकर 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहें।

यह मामला भोपाल के रहने वाले शिकायतकर्ता सुनील अहिरवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मेरठ में ललिता गौतम हत्या मामले में न्याय दिलाने की मांग को लेकर आयोजित किए गए एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बिना किसी उकसावे के बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया जिससे कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आईं।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि इस घटना से जुड़े और व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहले से ही पुलिस हिरासत में ले लिए गए असहाय लोगों को बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं जो सीधे तौर पर हिरासत में यातना देने का मामला है। उन्होंने इसे कानून के शासन के पूरी तरह विफल होने और मानवीय गरिमा के गंभीर उल्लंघन का उदाहरण बताया है।

अपनी शिकायत में सुनील अहिरवार ने आयोग से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मंगाने स्वतंत्र जांच शुरू करने और वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कर जिम्मेदार लोगों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी घायलों को तुरंत चिकित्सा पुनर्वास और कानूनी वित्तीय मुआवजा दिलाने तथा दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द आपराधिक और विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है।

Source: <https://www.abplive.com/news/nhrc-seeks-report-from-uttar-pradesh-dgp-and-home-secretary-on-alleged-police-lathi-charge-in-meerut-3157722>

हिंदी न्यूज़न्यूज़मेरठ लाठीचार्ज मामले में NHRC सख्त, यूपी के DGP और गृह सचिव से मांगी रिपोर्ट

मेरठ लाठीचार्ज मामले में NHRC सख्त, यूपी के DGP और गृह सचिव से मांगी रिपोर्ट

Meerut Lathicharge: आयोग ने उत्तर प्रदेश के DGP और प्रमुख सचिव (गृह) से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें पूछा गया है कि पुलिस को बल प्रयोग की जरूरत क्यों पड़ी

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह | Updated at : 10 Jul 2026 12:49 PM (IST)

मेरठ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित लाठीचार्ज की घटना अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंच गई है। आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) और प्रमुख सचिव (गृह) को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

क्या है पूरा मामला?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ, जिसकी अध्यक्षता सदस्य प्रियंक कानूनगो कर रहे हैं, ने डॉ. अंबेडकर जन कल्याण समिति की ओर से दी गई शिकायत पर संज्ञान लिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मेरठ में एक शांतिपूर्ण जन प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बिना किसी उकसावे के प्रदर्शनकारियों पर बर्बर लाठीचार्ज किया।

यह भी पढ़ें: ईरान ने पाकिस्तान के बाद सऊदी लगाया फोन, इधर ट्रंप-नेतन्याहू में हुई बात, अब रुकेगी या भड़केगी जंग?

प्रदर्शन क्यों हो रहा था?

शिकायत के मुताबिक, यह प्रदर्शन एक हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आईं।

NHRC ने क्या पूछा?

आयोग ने उत्तर प्रदेश के DGP और प्रमुख सचिव (गृह) से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें पूछा गया है कि पुलिस को बल प्रयोग की जरूरत क्यों पड़ी, प्रदर्शनकारियों को कितनी और कैसी चोटें आईं, पुलिस कार्रवाई का आधार क्या था और घायलों को क्या चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई।

जवाबदेही पर भी सवाल

NHRC ने यह भी जानकारी मांगी है कि यदि जांच में पुलिस की ओर से किसी तरह की ज्यादाती या नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है या की जाएगी। आयोग ने मामले को मानवाधिकारों के संभावित उल्लंघन से जुड़ा बताते हुए पूरी रिपोर्ट तलब की है।

Source:

<https://www.bhaskar.com/local/haryana/sonipat/gohana/news/haryana-brick-kilns-forced-labour-nhrc-officials-scolded-update-138408540.html>

Hindi NewsLocalHaryanaSonipatGohanaHaryana Brick Kilns Forced Labour: NHRC Scolds Officials

हरियाणा में बंधुआ मजदूरी के 86 मामलों पर NHRC सख्त: अधिकारियों को लगाई फटकार; ईट-भट्टों की जांच पर उठाए सवाल
सोनीपत 15 घंटे पहले

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में स्थित ईट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी के 86 मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। इन मामलों को लेकर आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन सुनवाई आयोजित की गई। इस सुनवाई में आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव, श्रम आयुक्त और सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट (DM) शामिल हुए।

आयोग ने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर जांच में पाई गई कमियों को लेकर फटकार लगाई। उन्हें नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन ने सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि अधिकतर मामलों में संबंधित अधिकारियों ने दस्तावेजों और अभिलेखों की ठीक से जांच नहीं की थी।

पुख्ता रिकॉर्ड न होने के कारण अधिकारियों के पास श्रमिकों को बंधुआ मजदूर घोषित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे। न्यायमूर्ति ने सभी अधिकारियों से बंधुआ मजदूरी के मामलों से निपटते समय सतर्क रहने का आग्रह किया।

SOP और 'एडवाइजरी 2.0' का पालन अनिवार्य

आयोग ने स्पष्ट किया कि शिकायतों की जांच के लिए टीम का गठन करते समय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 14 मई 2026 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अक्षरशः पालन किया जाए। यह SOP बंधुआ मजदूरों की पहचान, बचाव और अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए तय की गई है।

साथ ही, एनएचआरसी के संयुक्त सचिव समीर कुमार ने 'बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास हेतु जारी सलाह 2.0' (Advisory 2.0) के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया।

ATR की समीक्षा और हेल्पलाइन की मांग

सुनवाई के दौरान आयोग ने हरियाणा के जिला प्रशासकों द्वारा प्रस्तुत की गई एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) की विस्तृत समीक्षा की। न्यायमूर्ति रामासुब्रमणियन ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि बंधुआ मजदूरी की घटनाओं पर प्रभावी नज़र रखने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू की जानी चाहिए, ताकि पीड़ित श्रमिक जरूरत पड़ने पर सीधे और तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें।

सरकार ने दिया पूर्ण अनुपालन का आश्वासन

आयोग के कड़े रुख के बाद, हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी और श्रम आयुक्त विजयकुमार भाविकट्टी ने मानवाधिकार आयोग को आश्वस्त किया कि सभी 86 मामलों की नए सिरे से गहन समीक्षा की जाएगी और जल्द ही आवश्यक जानकारी व विस्तृत रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

उन्होंने NHRC को पूरा भरोसा दिलाया कि बंधुआ मजदूरी से संबंधित मामलों में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए देश की सर्वोच्च

न्यायालय (Supreme Court) के निर्देशों और सभी लागू कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस सुनवाई के दौरान संयुक्त सचिव समीर कुमार और संयुक्त रजिस्ट्रार (कानून) इंद्रजीत कुमार सहित आयोग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

DATE	CHANNEL	TIME	DETAILS	DURATION	PROGRAM	AUTHOR	PERSONALITY
10.07.2026	News18 India	15:30	Lalit Gautam Case: मेरठ में बवाल, NHRC की एंट्री, चंद्रशेखर आजाद की पुलिस से नोकझोंक -मेरठ की बीए छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मामले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ और एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें SSP एक प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारियां कीं। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मामले का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के DGP और गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है। इसी बीच मेरठ जाते समय चंद्रशेखर आजाद की पुलिस से टोल प्लाजा पर तीखी नोकझोंक भी हुई।	07:11 Min	Breaking News	Nishant	
10.07.2026	Sathiyam News	15:00	NHRC issues notice to U.P. DGP, Home Secretary over alleged police excess during Meerut protest Complaint with NHRC says police carried out an 'unprovoked, brutal lathi-charge' on participants in what was described as a peaceful public demonstration demanding justice in the murder case of a Dalit woman, that left several protesters with severe injuries	00:38 Min	Breaking News	Abc	

10.07.2026	India 24x7	18:00	Meerut Lathi Charge: NHRC सख्त, DGP और गृह सचिव से 15 दिन में मांगी रिपोर्ट मेरठ लाठीचार्ज मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के DGP और प्रमुख गृह सचिव से 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज और SSP अविनाश पांडे द्वारा प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने के आरोपों पर भी NHRC ने गंभीरता दिखाई है। जानिए पूरे मामले की ताज़ा अपडेट और अब आगे क्या हो सकता है।	07:50 Min	Breaking News	Abc	
10.07.2026	TV9 Bharatvarsh	19:00	Lalita Gautam Murder Case: मेरठ लाठीचार्ज पर NHRC का एक्शन DGP से मांगी रिपोर्ट!	04:44 Min	Breaking News	Abc	

10.07.2026	News18 India	21:00	मेरठ लाठीचार्ज मामले पर ऐक्शन -उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक रोज़ पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त हो गया। UP के DGP और गृह विभाग से रिपोर्ट मांग ली। एक रोज़ पहले मेरठ के कलेक्टरेट गेट के सामने प्रदर्शन हुआ था। दलित समुदाय की एक छात्रा की हत्या के मामले को लेकर। लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां चला दी थीं। उन्हें खदेड़ दिया था। वो लोग जिस छात्रा के लिए इंसान की मांग कर रहे थे, उसका शव क़रीब दो महीने पहले गन्ने के एक खेत से मिला था। शव मिला तो हंगामा मच गया था। घरवालों ने बवाल कर दिया था। तीन लड़कों पर हत्या के आरोप लगाए थे। पुलिस ने उनमें दो को गिरफ़्तार कर लिया था। जेल भेज दिया था। पुलिस ने जानकारी दी कि मुख्य आरोपी ने जुर्म क़बूल भी कर लिया था। लेकिन एक रोज़ पहले पीड़ित लड़की के परिवार के कुछ लोग धरने पर बैठ गए। मेरठ के कमिश्नरी पार्क में। मांग की कि मामले की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। आरोपियों को फांसी की सज़ा मिले।	08:49 min	Sau Baat ki Baat	Kishore Ajwani	
10.07.2026	News18 India	14:00	UP में Lalita Gautam Hatyakand पर सियासत गर्माई -मेरठ के चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड पर सियासत गर्मा गई है... दलित संगठनों के विरोध-प्रदर्शन के बीच अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए ... NHRC ने यूपी DGP और गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी..	02:14 Min	Breaking News	Abc	

10.07.2026	ABP NEWS	17:00	राम मंदिर ट्रस्ट विवाद पर विपक्ष को BJP का जवाब -मेरठ के लक्ष्मी गौतम हत्याकांड, पुलिस कार्रवाई, एनएचआरसी के नोटिस और राम मंदिर से जुड़े विवाद पर बीजेपी सांसद डॉ. भोला सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी और सरकार किसी भी दोषी को नहीं बख्खेगी।	04:59 Min	Breaking News	Abc	
10.07.2026	Bharat Samachar	13:00	Baruipur Case: 3 और आरोपी गिरफ्तार, CM Suvendu Adhikari आज पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात -बारुईपुर गैंगरेप और हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या और बढ़ गई है। वहीं, मॉब लिंगिंग में मारे गए निर्दोष इंद्रजीत मंडल मामले की जांच भी तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज बारुईपुर का दौरा करेंगे। वे गैंगरेप पीड़िता के परिवार और इंद्रजीत मंडल के परिजनों से मुलाकात करेंगे। साथ ही सूर्यपुर में नए पुलिस आउटपोस्ट का उद्घाटन भी करेंगे, जिसका निर्माण पीड़ित परिवार की मांग के बाद रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है।	03:00 Min	Breaking News	Abc	

10.07.2026	News18 Bangla	13:18	Baruipur Incident : Police have arrested the prime accused in the mob lynching case after conducting overnight raids across multiple locations in West Bengal. The main accused, Shariful Mallik, was arrested from Digha, while Abu Siddik Sardar was apprehended from Canning. Another accused, Shamim Ali Khan, was arrested from Baruipur.	02:54 Min	Breaking News	Abc	
10.07.2026	News18 Kerala	17:00	Perumbavoor Mob Attack : Police have registered a case in the mob lynching incident in Perumbavoor. Based on the complaint filed by the youths, a case has been filed against six identifiable persons. The complaint alleges that they were assaulted and their heads were shaved after being accused of being ganja sellers.	21:48 Min	Breaking News	Arpita	
10.07.2026	Manorama News	19:00	Perumbavoor Mob Trial: Bail Granted to All Six Accused -The Perumbavoor Magistrate's Court has granted conditional bail to six people arrested in the Perumbavoor mob lynching case. Four of the accused are Toofan Warriors.	01:33 Min	Breaking News	Abc	
10.07.2026	News18 Bangla	14:00	Police have arrested the prime accused in the mob lynching case after conducting overnight raids across multiple locations in West Bengal. The main accused, Shariful Mallik, was arrested from Digha, while Abu Siddik Sardar was apprehended from Canning. Another accused, Shamim Ali Khan, was arrested from Baruipur.	02:15 Min	Breaking News	Abc	

10.07.2026	asianetnews	15:30	Police beat up a young man in Badiyaduka; Police brutality was on the charge of stealing a lock Kasaragod -A young man was beaten up by the police in Badiyadukka, Kasaragod; The police brutality was on the charge of stealing a lock; Ajith Kumar, who was beaten up, has decided to take legal action against the police	03:45 Min	Breaking News	Abc	
10.07.2026	Thanthi TV	14:00	Sai Krishna Custodial Death -The Special Investigation Team (SIT) probing the alleged custodial death of Gade Sai Krishna has filed a petition in the Supreme Court, seeking permission to question the accused in full and asking the apex court to relax the conditions set by the Andhra Pradesh High Court.	13:25 Min	Breaking News	Abc	
10.07.2026	asianetnews	19:20	When the anesthesia was given, the baby's eyes popped up and he lost consciousness. They wanted money. The doctor said that if I wanted to come and take care of the baby, I would have to pay Rs 18,000 as a fee. My son had asked me whether my baby or my money was more important. Why was this dose of anesthesia given to a one and a half year old child?; Relatives in the death of a one and a half year old child	10:15 Min	Breaking News	Abc	

10.07.2026	Republic Bharat	18:00	भीलवाड़ा में 6 दिन में 5 प्रसूताओं की मौत! कोटा, बीकानेर और जोधपुर के बाद अब राजस्थान के भीलवाड़ा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। भीलवाड़ा के एमसीएच (MCH) अस्पताल में मात्र 6 दिन के भीतर 5 प्रसूताओं की मौत हो गई है। सभी महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और अब ओटी (Operation Theatre) की कल्चर रिपोर्ट पॉजिटिव आने से अस्पताल में खतरनाक बैक्टीरिया के संक्रमण का खुलासा हुआ है।	03:02 Min	Breaking News	Abc	
10.07.2026	Mediaone	19:00	1.5-Year-Old Boy Dies After Being Given Anesthesia for Stitches in Kerala Hospital -An 18-month-old boy who had remained in critical condition for five days after being given anaesthesia to stitch a cut lip died at a private hospital in Kannur on Friday, July 10.	02:18 Min	Breaking News	Garima	

